सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 279, नई दिल्ली । बुधवार, 18 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें, जो आपको महत्व देते हैं।

03 वरुण धवन ने दिल्ली में किया 'बेबी जॉन' का प्रमोशन
06 आईआईटी मद्रास के पास एक डिजिटल मानव मस्तिष्क एटलस तैयार है
08 राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह

सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने दिल्ली में पंजीकरण होने वाले तीन डीजल वाहनों को 15 साल तक चलने/ पंजीकरण की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल बढ़ा दिया डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन

संजय बाटला

नई दिल्ली। डीजल वाहन चलाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से डीजल वाहनों के पंजीकरण को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया।

बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कई कदम उठाए गए हैं जिसमें दिल्ली में डीजल वाहनों का 15 साल की उम्र होने पर भी 10 साल तक चलने की अनुमति भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है. दिल्ली में डीजल के वाहनों को 10 वर्ष से ज्यादा आयु पर चलने की अनुमति नहीं है यानी अगर कोई डीजल वाहन खरीदता है तो वह दिल्ली की सड़कों पर इसे सिर्फ 10 वर्ष तक ही चला सकता है।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। शीर्ष अदालत ने डीजल वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया लेकिन बढ़ोतरी सिर्फ एसपीजी के खास वाहनों के लिए ही दी।

शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई डीजल वाहनों की रजिस्ट्रेशन अवधि देश के सर्वोच्च अदाल की ओर से एक बड़ा फैसला दिया गया है इसके तहत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा दस्ते में शामिल किए जाने वाले तीन खास डीजल वाहनों को दिल्ली में चलने की अवधि को पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

एनजीटी की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी और इसमें मांग की गई थी कि डीजल वाहनों को लेकर जो नियम उसके मुताबिक 10 वर्ष में वाहनों को बंद किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान एसपीजी को राहत देते हुए तीन वाहनों के रजिस्ट्रेशन अवधि को बढ़ाने का निर्देश दे दिया। एसपीजी के सुरक्षा दस्ते में शामिल तीन बख्तरबंद विशेष वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने एनजीटी को भी निर्देश दिया है इन वाहनों के पंजीकरण/चलने की अवधि को पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाए, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह व्हीकल खास सुरक्षा समूह की तकनीकी और साजो-सामान का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन/ दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट की बेंच ने एसपीजी के 3 व्हीकल को सड़को पर चलने की अवधि को पूरे पांच वर्ष बढ़ा दिया.

एनजीटी की ओर से 22 मार्च 2023 को एसपीजी के इन वाहनों को दिल्ली की सड़को पर चलने की टाइमिंग बढ़ाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद एसपीजी ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने एसपीजी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन वाहनों की अवधि बढ़ा दी।

अगर ट्रांसपोर्टोंरों और ड्राइवरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें नितिन गडकरी : एबीटीए

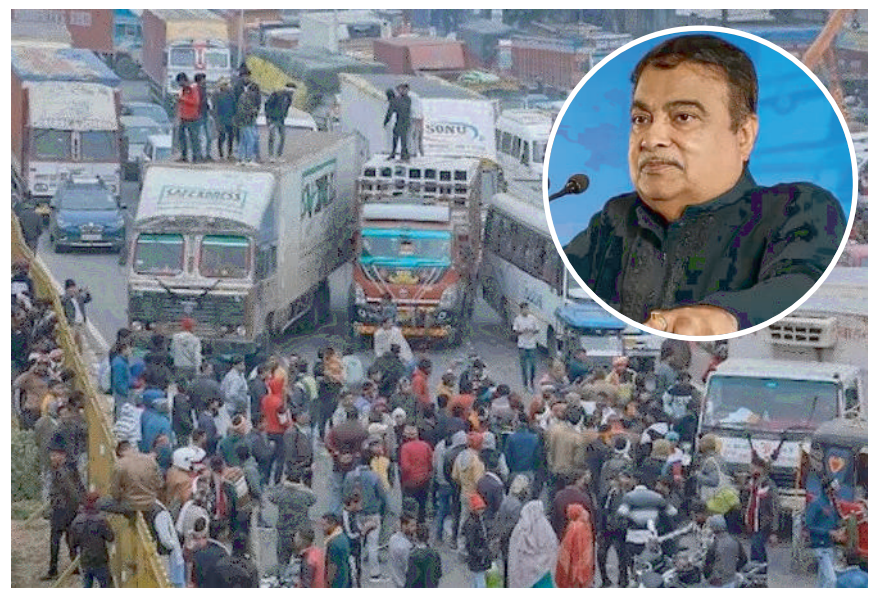

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में 27-28 नवंबर के राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं आने तथा ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों के प्रति उदासीन रवैए के कारण सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ काफी रोष है भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के शर्मा ने बताया की देश की काफी ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवर एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवरों की विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर मंत्रालय को अनगिनत पत्राचार करती हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री ट्रांसपोर्टोंरों की समस्याओं के प्रति बहुत ज्यादा उदासीनता रखते हुए पत्रों का जवाब देने की बजाय रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं जबकि देश की उन्नति एवं सेवा में ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवर विभिन्न प्रकार की परेशानियों एवं अपमान सहते हुए भी लगातार कार्य करते रहते हैं लेकिन गाड़ी मालिक गाड़ियों की किस्त और ड्राइवर की तनख्वाह समय पर न देने की वजह से दूसरे व्यवसाय में पलायन करने को मजबूर हैं एबीटीए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से ट्रांसपोर्टों और ड्राइवर की विभिन्न तरह की समस्याओं के समाधान एवं हमारी पुरानी मांग ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवर आयोग के गठन के लिए शीघ्र कदम उठाकर हमारे मांगों के प्रति सक्रिय भूमिका निभाए अन्यथा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बैठक में ड्राइवर विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जांगड़ा, के के सेठी, सुरेंद्र शर्मा, अनिल भारद्वाज, कमांडेंट ह्रदेश कुमार, हेतराम चौधरी, दिनेश पारीक, अशोक कुमार, नरेंद्र शर्मा, सुरेश यादव, जयपाल शर्मा, भजन लाल खिचड़, सत्यपाल भाटी, अजीत सिंह, राकेश कांटीवाल, राजेश शर्मा आदि उपस्थित थे।

अचानक व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस को बुराड़ी से झुल -झुली शिफ्ट करने के तुगलकी फरमान के खिलाफ हमारी टीम आदरणीय के के छाबड़ा जी के कुशल नेतृत्व ,राजू कक्कड़ भाई जी के तटस्थ मागदर्शन,भाई देवेंद्र यादव जी व सुभाष त्यागी जी के अथक प्रयास और भाई तुषार अरोड़ा व अन्य लोगों के सहयोग से हमने अब इस आंदोलन में जो भूमिका निभाई है उसका विवरण निम्न है,

1- क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव झा से निरंतर संपर्क

2- क्षेत्रीय सांसद श्री मनोज तिवारी को इस समस्या से अवगत कराया

3- भाई देवेंद्र यादव जी के सहयोग से पूर्व महापौर सरदार अवतार सिंह जी को अपनी समस्या से अवगत कराया

4- दिल्ली बी जे पी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा से वाहनों की फिटनेस में हो रही परेशानी से अवगत कराया

5- पूर्व महापौर अवतार सिंह जी के सहयोग से केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा से भी अपनी इस समस्या पर विचार किया

4-क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव झा जी के सहयोग से माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री मंत्री आतिशी जी को जल्दी इस परेशानी से निजात देने की सिपारिश की

6- पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी को भी अपनी इस विकट समस्या से अवगत कराया

7- नव नियुक्त दिल्ली परिवहन मंत्री श्री रघुवेंद्र शौकीन जी से भी अपनी इस समस्या को बताया

आप सभी ने भी जो इस व्यवसाय से जुड़े हो इस आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहुति दी है,,,,आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया,,,

और उम्मीद है, जब तक ये आंदोलन अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता,,,आप इसी प्रकार सहयोग करोगे,,,

विनोद नेगी
(अध्यक्ष, ग्रामीण सेवा परिवहन वेलफेयर एसोसिएशन रजि.)

बसों के लिए फिटनेस हेतु अपॉइंटमेंट न मिलने के कारण अनुचित उत्पीड़न

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। बस और कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन और गुरमीत सिंह तनेजा, अध्यक्ष (सीएमवीआर समिति) द्वारा आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बसों के लिए फिटनेस हेतु अपॉइंटमेंट न मिलने के कारण अनुचित उत्पीड़न की जानकारी हेतु पत्र के माध्यम से सूचित कर मदद की बात लिखी। इसमें इन्होंने बताया की

1. संदर्भः- केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 56: परिवहन वाहन की फिटनेस का प्रमाण पत्र

2. संदर्भः केंद्रीय मोटर वाहन नियम 62: फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता

हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि दिल्ली में परिवहन वाहनों की फिटनेस झुलझुली स्थित स्वचालित फिटनेस सेंटर द्वारा की जा रही है। दिल्ली में पंजीकृत परिवहन वाहनों की कुल संख्या इतनी अधिक है कि एक दिन में 180-200 परीक्षण करने की कुल क्षमता वाला एक ऐसा केंद्र पर्याप्त नहीं है। इसके कारण फिटनेस के लिए अपॉइंटमेंट मिलने में देरी हो रही है।

परिवहन वाहन मालिकों के लिए आय का स्रोत है और वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन किए बिना परिवहन वाहन मालिक अपने वाहन नहीं चला सकते हैं।

वर्तमान परिदृश्य में, दिल्ली में स्वचालित फिटनेस केंद्रों की कमी के कारण परिवहन वाहन मालिकों को फिटनेस के लिए अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है।

स्वचालित फिटनेस केंद्र पर अनिवार्य फिटनेस लागू होने का दुष्परिणाम यह है कि परिवहन वाहन मालिकों को रिश्वत देने की धमकी दी जाती है ताकि उनके वाहन परीक्षण में विफल न हों। यह उत्पीड़न और कानून के प्रावधान का दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

हम स्वचालित फिटनेस केंद्र में निरीक्षण अधिकारियों के हाथों में शिकार हैं क्योंकि हम उनके कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बसें चलाने वाले परिवहन वाहन मालिकों को फिटनेस टेस्ट करवाने के लिए स्लॉट की अनुपलब्धता के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गई है, जिससे प्रदूषण में कमी आई है।

हम अनुरोध करते हैं कि जब तक दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वचालित फिटनेस सेंटर नहीं बनाए जाते, तब तक किसी भी बस मालिक को स्लॉट की अनुपलब्धता की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लंबित फिटनेस टेस्ट की भरपाई के लिए रविवार को भी काम किया जाना चाहिए। बुराड़ी आरटीओ को भी टेस्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए और फिटनेस का प्रमाण पत्र देना चाहिए।

हम आग्रह करते हैं कि कोई भी परिवहन वाहन मालिक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में फिटनेस सेंटर की अनुपलब्धता के कारण कीमत का भुगतान न करे और वित्तीय नुकसान न उठाए।

धन्यवाद,

आपका,

बस और कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रसन्ना पटवर्धन अध्यक्ष, गुरमीत सिंह तनेजा, अध्यक्ष (सीएमवीआर समिति)

दिल्ली में ऑड-ईवन के लिए हो जाएं तैयार, क्या है नियम? पहले कब-कब लगा ये फॉर्मूला

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तिथि में पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-3 और 4 की सभी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह पर दिल्ली सरकार ऑड-ईवन लागू करने पर विचार कर रही है। आगे रिपोर्ट में समझिए आखिर ऑड-ईवन क्या होता है और कब-कब इसे दिल्ली में लागू किया गया?

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी में हालात चिंताजनक होने के चलते जल्द ही ऑड-ईवन का फॉर्मूला (What is Odd-Even Scheme) लागू किया जा सकता है। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह पर अभी दिल्ली सरकार ऑड-ईवन नियम पर विचार कर रही है।

दिल्ली सरकार ऑड-ईवन पर कर रही विचार

वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह पर दिल्ली सरकार अभी ऑड-ईवन लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन जब भी इसे लागू किया जाएगा, लोगों के सामने दफ्तर जाने की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।

दिल्ली-NCR फिर लागू हुई ग्रैप-3 और 4 की पाबंदियां

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) ने ग्रैप-3 और 4 लागू कर दिया है। इससे ग्रैप-3 और 4 की सभी पाबंदियां फिर लग गई हैं। अब ऐसे में कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

ग्रैप-3 के नियम

ग्रैप-3 के तहत दिल्ली-NCR में BS-3 पेट्रोल व BS-4 इंजन वाले चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई।

बीएस चार डीजल (BS-4 Diesel) वाले माल वाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक हाईब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए।

प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्य बंद रहेंगे।

निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

सभी स्टोन क्रसर बंद हो जाएंगे।

खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

अस्पताल, रेल, मेट्रो इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है।

ग्रैप-4 में ये प्रतिबंध होंगे लागू

दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लेकर पहुंचने वाली ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा सीएनजी, इलेक्ट्रिक व बीएस छह इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।

दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार के एचजीवी (भारी मालवाहक वाहन) पर रोक। सिर्फ आवश्यक सामान ढोने वाले एचजीवी वाहन को छूट रहेगी।

निर्माण और विध्वंस पर पूरी तरह रोक रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाएं इत्यादि सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य बंद रहेगा।

दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्कूलों में छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन व ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड़ में होगी।

सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश। एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करने का निर्देश।

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला ले सकती है।

एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें कॉलेज बंद, ऑड ईवेन लगाने और गैर जरूरी व्यवसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए बंद रखने का फैसला ले सकती हैं।

समझिए क्या है ऑड-ईवन नियम?

ऑड-ईवन नियम पहली बार वर्ष 2016 में प्रदूषण बढ़ने पर लागू किया गया था। इस नियम के तहत सड़कों पर निजी वाहन को वैकल्पिक दिन दिए जाते हैं, जिस दिन वो अपने वाहनों को सड़कों पर दौड़ा सकते हैं और वो दिन उनकी नंबर प्लेट के आखिरी अंक पर निर्भर करता है।

यह भी पढ़ें- Delhi Election 2025: दिल्ली चुनाव से पहले BJP से क्यों आगे हुई AAP? सामने आया केजरीवाल का मास्टर प्लान

ऑड-ईवन नियम

Odd Date (सम अंक)	Even Date (विषम अंक)
0	1
2	3
4	5
6	7
8	9

इससे पहले कब-कब लागू किया गया ऑड-ईवन प्लान

राजधानी दिल्ली में पहले भी ऑड-ईवन लागू किया जा चुका है। दिल्ली में सबसे पहले दिसंबर 2015 में ऑड-ईवन (Odd Even Rule) लागू किया गया था। इसके बाद जनवरी 2016 में ऑड-ईवन को लागू करने की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद 2019 में भी राजधानी में ऑड-ईवन लागू किया गया था। ऑड-ईवन लागू होने से प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलती है।

कुपोषण आज भी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है (द लैंसेट जर्नल रिपोर्ट)

आधुनिक युग में हमारी जीवनशैली में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं और आज हमारी खान-पान की आदतों में बहुत बदलाव हो चुके हैं। खान-पान भी समय पर नहीं किया जा रहा है, आधुनिक शहरी, भागम-भाग भरी जीवनशैली के साथ देर रात को खाना आज जैसे फैशन हो चुका है। दिन में भी न ब्रेकफास्ट का कोई समय है और न ही लंच का। आजकल तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के स्थान पर ब्रंच का कंसेप्ट भी भारतीय संस्कृति में जन्म ले चुका है। आज मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक कैलोरी का सेवन करता है और उस अनुरूप शारीरिक व्यायाम,कसरत, मेहनत आज आदमी नहीं करता। कहना ग़लत नहीं होगा कि अत्यधिक प्रसंस्कृत(डिब्बा बंद) भोजन, उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थ और पेय, तथा उच्च मात्रा में संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थ आज मनुष्य में अधिक वजन का कारण बन रहें हैं। हालांकि, आनुवंशिकी मोटापे का एक मजबूत घटक है,चीनी-मीठे, उच्च वसा वाले

इंजीनियर्ड जंक फूड्स, फास्ट फूड, हमारी भोजन की असमय करने की आदतें, वेस्टर्न कल्चर(पाश्चात्य संस्कृति) के बहुत से आहार, तथा बहुत बार विभिन्न पर्यावरणीय कारक भी मोटापा लाते हैं। वास्तव में मोटापा (ओबैसिटी) वो स्थिति होती है, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यहां तक कि यह आयु संभावना को भी घटा सकता है, मनुष्य की बीएमआई(शरीर द्रव्यमान सूचक) को प्रभावित कर सकता है। सच तो यह है कि मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे हृदय रोग(हार्टअटैक) , मधुमेह(डायबिटीज), निद्रा कालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर आदि आदि। सच तो यह है कि आज मोटापा दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह बहुत ही चिंतनीय है कि आज दुनिया में हर आठवां व्यक्ति मोटापे का शिकार है। क्या यह बहुत चिंताजनक नहीं है कि तीन दशकों में मोटापे (ओबैसिटी) की समस्या में चार गुना से भी अधिक इजाफा हुआ है। आज बड़े बुजुर्गों से लेकर महिलाओं, बच्चों को शामिल करते हुए सभी उम्र के लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है। आज शहरों में वज़न कंट्रोल करने के लिए अनेक जिम खुले हैं लेकिन हमारी जीवनशैली ऐसी हो चुकी है कि मोटापा कम होने का नाम तक नहीं ले रहा है। हम अपनी संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को आज अपना रहे हैं और आज हमारी भोजन पद्धति में जो बदलाव आए हैं, वे मोटापे के प्रमुख कारण हैं। आज क्रोनिक बीमारियों का कारण कुछ और नहीं बल्कि शरीर का मोटापा ही तो है। मोटापे के संदर्भ में द लैंसेट जर्नल का अध्ययन चौंकाने वाला है। जानकारी देना चाहूंगा कि द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार, दुनियाभर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों, किशोरों और वयस्कों की कुल संख्या एक

बिलियन (एक अरब) से अधिक हो गई है। शोधकर्ताओं ने यह बात कही है कि, साल 1990 के बाद से कम वजन वाले लोगों की घटती व्यापकता के साथ अधिकांश देशों में मोटापा के शिकार लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अन्य सहयोगियों के साथ इस वैश्विक डेटा के विश्लेषण में अनुमान लगाया है कि दुनियाभर के बच्चों-किशोरों में साल 1990 की तुलना में 2023 में, यानी तीन दशकों में मोटापे की दर चार गुना बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है यह चलन लगभग सभी देशों में देखा गया है।वयस्क आबादी में, महिलाओं में मोटापे की दर दोगुनी और पुरुषों में लगभग तीन गुना से अधिक हो गई।अध्ययन के अनुसार साल 2022 में 159 मिलियन (15.9 करोड़) बच्चे-किशोर और 879 मिलियन (87.9 करोड़) वयस्क मोटापे के शिकार पाए गए हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले तीन दशकों में वयस्कों में मोटापा दोगुना से अधिक हो गया है। वहीं, 5 से 19 साल के बच्चों और किशोरों में यह समस्या चार गुना बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अध्ययन में यह भी सामने आया कि 2022-23 में 43 फीसद वयस्क अधिक वजन वाले थे। इस अध्ययन के अनुसार 1990 से 2022 तक विश्व में सामान्य से कम वजन वाले बच्चों और किशोरों की संख्या में कमी आई है। इतना ही नहीं, यह स्टडी बताती है कि दुनियाभर में समान अवधि में सामान्य से कम वजन से जूझ रहे वयस्कों का अनुपात आधे से भी कम हो गया है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि यह अध्ययन कुपोषण के विभिन्न रूपों संबंधी वैश्विक रूझानों की विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहां यह भी कहना ग़लत नहीं होगा कि आज दुनिया के ग़रीब इलाकों, हिस्सों में करोड़ों लोग आज भी कुपोषण से पीड़ित हैं। बहरहाल, पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि रिसर्चर ने इस अध्ययन के लिए 190 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच वर्ष या उससे अधिक उम्र के 22 करोड़ से अधिक लोगों के वजन और लंबाई(बीएमआई) का विश्लेषण किया, जिसमें सामने आया है कि सामान्य से कम वजन वाली लड़कियों का अनुपात वर्ष 1990 में 10.3 फीसद से गिरकर 2023 में 8.2 फीसद हो गया और लड़कों का अनुपात 16.7 फीसद से गिरकर 10.8 फीसद हो गया है।अध्ययन में यह भी पाया गया कि कुपोषण की दर भी कई जगहों पर विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता

विभिन्न शैक्षिक सुधारों और नीतियों के बावजूद, भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले शैक्षणिक पथ और सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच की खाई के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। कई सुधारों के बावजूद, इन मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनी हुई है। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया की मांगों के अनुरूप कौशल प्रदान करना, जीवन के मील के पत्थर और आधुनिक चुनौतियों के लिए तत्परता बढ़ाना है।

-प्रियंका सौरभ

कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा में एकरूपता की नींव रखी और शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसने 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफ़ारिश की, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली में भविष्य के सुधारों के लिए मंच तैयार किया। इस नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य समानता में सुधार करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम पेश किया और व्यावहारिक कौशल विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर दिया। इस योजना का उद्देश्य पोषण मानकों में सुधार करना और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना था। एसएसए का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को ख़त्म करना था। आरटीई अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया, जिससे सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित हुई। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य सीखने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर शिक्षा को वास्तविक दुनिया की ज़रूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना था। इसने रटने की आदत से हटकर परियोजना-आधारित सीखने और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया।

समग्र शिक्षा अभियान एकीकृत योजना का उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करना था। इसने हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा के लिए स्कूलों को अनुदान प्रदान किया। एनईपी 2020 ने प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कक्षा 10 के बाद कठोर धाराओं को ख़त्म करने जैसे परिवर्तनकारी बदलावों का प्रस्ताव रखा। यह समग्र विकास के उद्देश्य से शिक्षा के मार्गों में बहु-विषयक सीखने और लचीलेपन पर ज़ोर देता है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियाँ क्षेत्रों में गुणवत्ता की असमानताएँ हैं। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में एक महत्त्वपूर्ण अंतर है, जहाँ कई ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढाँचे और योग्य शिक्षकों की कमी है। एएसईआर 2018 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 50% बच्चे ही बुनियादी पाठ पढ़ सकते हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता में असमानताओं को उजागर करता है। शिक्षा प्रणाली अक्सर सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे छात्र कार्यबल में आवश्यक व्यावहारिक नौकरी कौशल के लिए तैयार नहीं होते हैं।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिग्री वाले स्नातकों में अक्सर नौकरी-विशिष्ट कौशल की कमी होती है, जिससे उच्च बेरोजगारी दर होती है। प्रणाली अभी भी रटने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे सीमित आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमताएँ होती हैं। आईसीएसई और सीबीएसई में, परीक्षाएँ अनुप्रयोग-आधारित सीखने के बजाय सामग्री को याद करने पर केंद्रित होती हैं, जिससे रचनात्मक सोच में बाधा आती है। शिक्षक प्रशिक्षण की कमियाँ: शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण अंतर है, जो शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। शिक्षकों की कमी और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को पर्याप्त रूप से सम्बोधित करने में विफल रहने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की आलोचना की गई है। डिजिटल शिक्षा के विकास के बावजूद, तकनीकी बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त बना हुआ है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की पहुँच और डिवाइस की पहुँच अभी भी कम है, जिससे छात्रों का आधुनिक शैक्षिक उपकरणों से संपर्क सीमित हो जाता है।

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता वास्तविक दुनिया के कौशल के साथ संरेखण की मांग करती है। आमूलचूल परिवर्तन छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, शिक्षा को वास्तविक दुनिया की मांगों के साथ संरेखित कर सकता है। फ़िनलैंड की शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक कौशल और हाथों से सीखने पर ज़ोर देती है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों की अधिक सहभागिता और रोज़गार क्षमता होती है। आमूलचूल सुधार लचीले शिक्षा मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जिससे छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर अलग-अलग सीखने के मार्ग अपनाने की अनुमति मिलती है। जर्मनी की दोहरी शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा और अकादमिक शिक्षा के बीच संतुलन प्रदान करती है, जिससे रोज़गार क्षमता में सुधार होता है। अधिक छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव से छात्रों में रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और आलोचनात्मक तर्क को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) कार्यक्रम रचनात्मकता, संस्कृति और संज्ञानात्मक कौशल सहित छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

आमूलचूल परिवर्तन उच्च-दांव वाली परीक्षाओं से दूर जा सकता है और अधिक निरंतर मूल्यांकन विधियों को अपना सकता है, जिससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम हो सकता है। सिंगापुर ने छात्रों के प्रदर्शन को मापने, तनाव को कम करने और सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन रणनीतियों को लागू किया है। आमूलचूल परिवर्तन से पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा को शामिल किया जा सकता है, जिससे पहुँच और सहभागिता बढ़ सकती है। कौशल-आधारित शिक्षा को शामिल करने जैसे पारंपरिक सुधारों से परे अभिनव समाधान। शुरुआती चरण में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-आधारित शिक्षा शुरू करने से छात्रों को व्यावहारिक क्षमताओं से लैस किया जाएगा, जिससे वे कार्यबल के लिए तैयार होंगे। दक्षिण कोरिया तकनीकी शिक्षा को मिडिल स्कूल से अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत करता है, जिससे एक कुशल कार्यबल तैयार होता है। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सीखने का संयोजन शैक्षिक विभाजन को पाट सकता है, जिससे जुड़ाव और पहुँच बढ़ सकती है।

स्कूलों में मिश्रित शिक्षा दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को आमने-सामने बातचीत से लाभान्वित करते हुए डिजिटल सामग्री तक पहुँचने की अनुमति देती है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग स्कूलों के लिए बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षण और संसाधनों को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में। ब्रिटिश काउंसिल भारतीय राज्यों के साथ मिलकर शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार और वैश्विक शिक्षण मानकों को पेश करती है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर शिक्षण परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के लिए: जापान ने अपने पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को एकीकृत किया है, जिससे छात्रों के कल्याण और प्रदर्शन में सुधार हुआ है। स्थानीयकृत शिक्षा मॉडल: क्षेत्रीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप शिक्षा प्रणालियों को तैयार करने से जुड़ाव और प्रासंगिकता में सुधार होगा।

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए आमूलचूल सुधारों की आवश्यकता है। फिनलैंड के छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण और दक्षिण कोरिया के व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, भारत भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए NEP 2020 के दृष्टिकोण के साथ मिलकर समावेशी और टिकाऊ शैक्षिक परिणाम प्राप्त कर सकता है।

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

एक महीने तक रोजाना पिएं एक गिलास मेथी का पानी

सदियों से आयुर्वेद में मेथी का इस्तेमाल पाचन कोलेस्ट्रॉल और सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। इसकी सब्जी या पराठे तो सर्दियों में आप भी खूब खाते होंगे लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर एक महीने तक रोजाना एक गिलास मेथी का पानी पिया जाए तो इससे सेहत में कैसे हैरतअंगेज सुधार देखने को मिल सकते हैं। आइए जानें।

नई दिल्ली। मेथी में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। जब मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखा जाता है तो इसके पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं, जिससे यह और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है।

क्या आप जानते हैं कि रोजाना मेथी का पानी पीने से आपकी सेहत में कई तरह के सुधार हो सकते हैं? जी हां, मेथी एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि कई बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि रोज एक महीने तक एक गिलास मेथी का पानी पीने से सेहत को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं और इसे तैयार करने का सही तरीका क्या है।

कैसे बनाएं मेथी का पानी?

रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में दो चम्मच मेथी दाना डालकर इसे ढंक दें। सुबह खाली पेट इस पानी को पी लें। एक महीने तक रोजाना ऐसा करने से आपको सेहत से जुड़े कई फायदे मिल सकते हैं।

रोजाना मेथी का पानी पीने के फायदे

डाइजेशन को बेहतर बनाए

मेथी में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। रोजाना एक महीने तक मेथी का पानी पीने से कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। बता दें, मेथी में मौजूद एंजाइम्स डाइजेशन को आसान बनाते हैं और खाने को अच्छे से पचाने में मदद करते हैं।

वेट लॉस को आसान बनाए

मेथी में मौजूद कुछ तत्व शरीर में मौजूद फैट को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही, यह भूख को कम करके भी वजन घटाने में मददगार होता है। मेथी का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर में कैलोरी बर्न होने की स्पीड तेज होती है।

यह भी पढ़ें- किसने कहा हर किसी के लिए फायदेमंद है मेथी का पानी? ये 5 लोग भूलकर भी न करें इसे पीने की गलती

ब्लूस्ट करे इम्युनिटी

मेथी में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक महीने तक रोजाना एक गिलास मेथी का पानी पीने से सर्दी, जुकाम जैसी छोटी-मोटी बीमारियों से बचा जा सकता है।

शुगर लेवल को करे कंट्रोल

मेथी में मौजूद कुछ तत्व ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए मेथी का पानी बेहद फायदेमंद होता है। बता दें कि यह इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कम करता है।

समान पैदावार के साथ स्वास्थ्य जोखिम कम करेगी प्राकृतिक खेती

किसानों की खाद की मांग को पूरा करने के लिए शहरी गीले कचरे से खाद बनाने को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में शामिल करें। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन: स्थानीय खाद बनाने के समाधानों के लिए शहर-किसान भागीदारी को बढ़ावा दें। खाद बनाने की तकनीक और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मज़बूत करें। जन जागरूकता और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण प्रथाओं को बढ़ाएँ। खेतों पर खाद बनाने के बुनियादी ढांचे के लिए सब्सिडी प्रदान करें। खेतों में सीधे अपशिष्ट वितरण को प्रोत्साहित करके यूएलबी के लिए परिचालन लागत कम करें।

-डॉ सत्यवान सौरभ

25 नवंबर, 2024 को भारत सरकार ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और एक करोड़ किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य जैविक खेती की ओर बढ़ रहे किसानों को प्रशिक्षित करना और उनका समर्थन करना है, जिसमें गाय के गोबर से बनी खाद और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य गैर-रासायनिक उर्वरकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ इसका एकीकरण कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अभिनव समाधान प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों ने पारंपरिक खेती करने वालों के समान ही पैदावार की सूचना दी। कई मामलों में, प्रति फ़सल अधिक पैदावार की भी सूचना मिली। चूंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। भोजन में पोषण घनत्व अधिक होता है और इसलिए यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।

प्राकृतिक खेती बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत कम कार्बन और नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ पानी का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य लागत में कमी, कम जोखिम, समान पैदावार, अंतर-फसल से आय के कारण किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करके खेती को व्यवहार्य और आकांक्षापूर्ण बनाना है। विभिन्न फसलों के साथ काम करके जो एक-दूसरे की मदद करते हैं और वाष्पीकरण के माध्यम से अनावश्यक पानी के नुक़सान को रोकने के लिए मिट्टी को कवर करते हैं, प्राकृतिक खेती 'प्रति बूंद फसल' की मात्रा को अनुकूलित करती है।

भारत में सालाना 5.8 करोड़ टन ठोस कचरा पैदा होता है, जिसमें 1 करोड़ टन जैविक खाद बनाने की क्षमता है। इसके बावजूद, अलग-अलग कचरे से शहरी खाद को अभी तक एकीकृत नहीं किया गया है, जो सालाना 15-20 लाख किसानों की खाद की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। अप्रसंस्कृत नगरपालिका अपशिष्ट अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के पास लैंडफिल में समाप्त हो जाता है, जिससे पर्यावरण क्षरण और मीथेन उत्सर्जन होता है। शहरी स्थानीय निकाय केवल 30-40% कचरे का प्रसंस्करण करते हैं, वे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को क्रियाशील रखने के लिए परिचालन सब्सिडी पर निर्भर रहते हैं।

जैविक खाद की आवश्यकता 2-3 टन प्रति एकड़ है, जो

100-150 किलोग्राम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता से कहीं अधिक है। परिवहन लागत जैविक खाद को इसकी कम क़ीमत (₹2, 000-3, 000 प्रति टन) के बावजूद किसानों के लिए कम सुलभ बनाती है। यह मॉडल अलग किए गए शहरी गीले कचरे को खेत की भूमि से जोड़ता है, जिससे खेतों पर सीधे खाद बनाना संभव हो जाता है। यह टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हुए अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करता है। शहरी स्थानीय निकाय अलग किए गए गीले कचरे को अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों या लैंडफिल के बजाय सीधे खेतों में पहुँचाते हैं। किसान पारंपरिक गड्ढा खाद बनाने के तरीकों का उपयोग करते हैं, गीले कचरे को गोबर के घोल और जैव-संस्कृतियों के साथ मिलाकर 2-3 महीनों के भीतर जैविक खाद का उत्पादन करते हैं। 1 लाख की आबादी वाला एक शहर प्रतिदिन 10-15 टन गीला कचरा उत्पन्न करता है, जो एक किसान के फ़सल चक्र के लिए प्रतिदिन 3 टन खाद बनाने के लिए पर्याप्त है। अपने खेतों पर निःशुल्क जैविक खाद तक पहुँच, परिवहन और इनपुट लागत में कमी। मिट्टी की सेहत में सुधार और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी। परिचालन सब्सिडी (टिपिंग शुल्क) पर बचत। अपशिष्ट प्रसंस्करण दक्षता में वृद्धि और मीथेन उत्सर्जन में कमी। लैंडफिल अपशिष्ट और सम्बंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के साथ इसके बहुत से फायदे हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहर-किसान भागीदारी (एसडब्ल्यूएम) ने 200 से अधिक किसानों को 2, 300 टन अलग-अलग गीले कचरे की आपूर्ति की, जिससे 600 टन जैविक खाद का उत्पादन हुआ। रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 50-60 टन की कमी। खाद बनाने से पहले और बाद में कठोर परीक्षण के माध्यम से मिट्टी की सेहत में सुधार हुआ जर्मनी में वैश्विक स्तर पर सबसे उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में से एक है, जो एक परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है। जैविक कचरे को स्रोत पर अलग किया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले खाद और बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। जापान ने ताकाकुरा खाद बनाने की विधि विकसित की है, जो घरेलू कचरे का उपयोग करके एक विकेन्द्रीकृत खाद बनाने की तकनीक है। यह विधि शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाई जाती है। स्वीडन ने जैव-चक्र खेती का मॉडल अपनाया है, जहाँ शहरी जैविक कचरे का उपयोग जैव-उर्वरक और बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है। सिंगापुर ने जैविक कचरे को टिकाऊ तरीके से प्रबंधित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर खाद बनाने के केंद्र स्थापित किए हैं।

किसानों की खाद की मांग को पूरा करने के लिए शहरी गीले कचरे से खाद बनाने को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में शामिल करें। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन: स्थानीय खाद बनाने के समाधानों के लिए शहर-किसान भागीदारी को बढ़ावा दें। खाद बनाने की तकनीक और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मज़बूत करें। जन जागरूकता और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण प्रथाओं को बढ़ाएँ। खेतों पर खाद बनाने के बुनियादी ढांचे के लिए सब्सिडी प्रदान करें। खेतों में सीधे अपशिष्ट वितरण को प्रोत्साहित करके यूएलबी के लिए परिचालन लागत कम करें। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) और शहर-किसान भागीदारी मॉडल भारत की कृषि और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक करोड़ किसानों को समर्थन देने के एनएमएनएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, यूएलबी और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे कृषि, शहरी शासन और पर्यावरण के लिए जीत-जीत का परिणाम सुनिश्चित हो सके।

यमुना दिल्ली की जीवन रेखा या प्रदूषण का शिकार?

यमुना नदी दिल्ली की जीवन रेखा है लेकिन प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण यह बर्बाद हो गई है। इस लेख में यमुना की वर्तमान स्थिति प्रदूषण के कारणों सरकारी प्रयासों और नदी के कायाकल्प के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है। जानें कैसे यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं।

नई दिल्ली। यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है। इसका पानी दिल्लीवासियों का प्यास बुझाने के साथ उनके सुख समृद्धि में सहायक रहा है। मछली पालन, खेतीबाड़ी सहित सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक गतिविधियों से लोगों का जीविकोपार्जन होता था, परंतु अब स्थिति बदल गई है। अनियोजित विकास, अतिक्रमण व भ्रष्टाचार के कारण यमुना मृत प्राय हो गई है।

इससे राजधानी में पेयजल संकट, भूजल दूषित होने और पारिस्थितकी तंत्र को नुकसान हो रहा है। इसका दुष्प्रभाव दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से अक्सर दिल्ली में जल आपूर्ति बाधित होती है। यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने के नाम पर वर्षों से राजनीति हो रही है।

प्रत्येक चुनाव में यह मुद्दा बनता है। नदी को साफ करने के लिए वर्ष 1993 में पहला यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। राजधानी में यमुना पल्ला से ओखला बैराज तक 48 किलोमीटर के दायरे में बहती है।

वजीराबाद से असगरपुर गांव तक 26 किलोमीटर का हिस्सा नदी की कुल लंबाई का मात्र दो प्रतिशत है, परंतु यह इसके 76 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की मासिक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में यमुना के पानी की गुणवत्ता पहले से अधिक खराब हुई है।

फेकल कोलीफार्म का स्तर पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है। यह प्रदूषण पानी में मल-मूत्र मिलने से होता है। इससे स्पष्ट है कि नदी में अनुपचारित सीवेज गिर रहा है। पानी में फेकल कोलीफार्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर 500 सर्वाधिक संभावित संख्या (एमपीएन) होना चाहिए।

इसका स्तर 2,500 एमपीएन पहुंचने पर यह उपयोग लायक नहीं रह जाता है। यमुना जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो पल्ला में फेकल कोलीफार्म का स्तर मात्र 1,100 एमपीएन रहता है। वहीं, असगरपुर में यह 79,00,000 एनपीएन तक पहुंच गया है।

असगरपुर से पहले शाहदरा व तुगलकाबाद ड्रेन यमुना में गिरता है। नदी के पानी को स्वच्छ

बनाए रखने के लिए घुलित ऑक्सीजन (डीओ) की मात्रा अधिकांश स्थानों पर शून्य हो गया है। जैव रासायनिक आक्सीजन मांग (बीओडी) भी स्वीकार्य पांच मिलीग्राम प्रति लीटर की तुलना में बहुत अधिक हो गया है।

स्वच्छ यमुना के लिए सरकारी प्रवास

यमुना एक्शन प्लान चरण-प्रथम

अप्रैल 1993 में शुरू हुआ और इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। वर्ष 2002 में शुरू। कुल व्यय 682 करोड़ रुपये।

यमुना एक्शन चरण-द्वितीय

वर्ष 2012 में शुरू कुल व्यय 1,514.70 करोड़ रुपये।

यमुना एक्शन प्लान चरण तृतीय

अनुमानित खर्च 1,656 करोड़ रुपये है। इस चरण में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर का पुनर्वास और उन्नयन शामिल है।

वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये और यमुना एक्शन प्लान-3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये दिए गए थे।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से 700 करोड़ रुपये यमुना की साफ-सफाई पर खर्च किया।

जल शक्ति मंत्रालय ने 11 परियोजनाओं के लिए 2361.08 करोड़ रुपये दिए।

यमुना नदी के कायाकल्प के लिए एनजीटी द्वारा जनवरी, 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में पिछले वर्ष उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की थी। नजफगढ़ ड्रेन सहित यमुना के कुछ क्षेत्र की सफाई अभियान शुरू किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्य सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

ओखला में बन रहे एशिया का सबसे बड़े एसटीपी का काम पूरा हो गया है। इससे 124 एमजीडी सीवेज शोधित हो सकेगा। कोंडली और सोनिया विहार में भी एसटीपी का काम भी लगभग पूरा हो गया है। 20 एसटीपी का उन्नयन कार्य चल रहा है।

कालिंदी कुंज के नजदीक जैव विविधता पार्क सहित यमुना तट को संवारने के लिए अस्तिता ईस्ट, बांसेरा जैसे 10 परियोजनाओं पर काम। नदी और इसके तट साफ होने से पर्यटन व अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

बीओडी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम और डीओ 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक करने का लक्ष्य है। दिल्ली में अभी बीओडी कई स्थानों पर 73 मिलीग्राम प्रति लीटर और डीओ शून्य तक है।

दिल्लीवासी हो रहे हैं बीमार

नदी में प्रदूषण बढ़ने से इसके तटवर्ती क्षेत्र की मिट्टी में जहर घुल रहा है। भूजल दूषित होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। नदी किनारे उपजी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सब्जी में लेड की मात्रा 0.1 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह 28.06 पीपीएम तक पाई गई। कैडियम की स्वीकृत मात्रा 0.1 से 0.2 पीपीएम की तुलना में 3.42 पीपीएम और पारा एक पीपीएम की जगह 139 पीपीएम तक मिला है। इनके सेवन से याददाश्त संबंधी परेशानी, फेफड़े, मस्तिष्क और पेट के कैंसर सहित अन्य गंभीर परेशानी हो सकती है।

122 छोटे-बड़े नाले यमुना में गिरते हैं, 22 नालों में से 10 का पानी ही शोधित हो रहा।

37 एससीटी राजधानी में लगाए गए हैं, अधिकांश मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

48 किमी के दायरे में यमुना दिल्ली में यमुना पल्ला से ओखला बैराज तक बहती है।

70 प्रतिशत प्रदूषण यमुना में नजफगढ़ ड्रेन और 30 प्रतिशत गुरुग्राम के तीन नालों से।

76 प्रतिशत प्रदूषण वजीराबाद से असगरपुर तक 26 किलोमीटर क्षेत्र में ही होता है।

वरुण धवन ने दिल्ली में किया 'बेबी जॉन' का प्रमोशन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। हाल ही में वरुण धवन अपनी आने वाली फिल्म 'बेबी जॉन' के प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे थे। यहां के द इंपीरियल होटल में प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कलीज द्वारा निर्देशित यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म का ट्रेलर 'बेबी जॉन' की दुनिया की झलक दिखाता है, जो एक्शन, मनोरंजन, हास्य और थिरकने वाले ट्रैक का एक बेहतरीन संयोजन है। दिग्गज एस. थमन का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर ट्रेलर को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है, जिससे दर्शक और अधिक देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं।

अपनी इस फिल्म के बारे में वरुण धवन ने कहा, ''बेबी जॉन' का हिस्सा बनकर मैं बेहद रोमांचित हूं। यह फिल्म एक गहरी भावनात्मक और शक्तिशाली यात्रा है और इस विशेष किरदार को जीवंत करना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। ट्रेलर इस कहानी की तीव्रता और दिल की एक झलक मात्र है और मैं दर्शकों द्वारा इसे बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।' वरुण ने आगे कहा, 'इस प्रोजेक्ट पर काम करना वाकई खास अनुभव रहा है और मैं इस अनुभव को सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं।' मुराद खेतानी, प्रिया एटली और ज्योति देशपांडे द्वारा निर्मित, 'बेबी जॉन' एक बड़ा सिनेमाई ड्रामा है, जिसे आप मिस करने की गलती नहीं कर सकते।

दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिकी नागरिक से ठगी, बदमाशों ने ऐसे बुना जाल; जांच में जुटा कस्टम विभाग

आईजीआई एयरपोर्ट पर अमेरिका से आए यात्री से कस्टम अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। कस्टम विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पर दूसरे मामला हरिनगर से है। यहां पर पुलिसकर्मियों ने एक फ्लैट में घुसकर छात्रों से लूटपाट की। जबकि पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर अमेरिका के फ्लोरिडा से आए एक यात्री से कुछ लोगों ने कस्टम अधिकारी बनकर ठगी कर डाली। पीड़ित यात्री के दोस्त ने इस पूरे प्रकरण को एक्स पर बयां किया और पोस्ट को दिल्ली कस्टम व पीएमओ को टैग कर दिया।

कस्टम ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह मामला धोखाधड़ी का लग हो रहा है। कस्टम ने पोस्ट करने वाले शख्स से इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है और कहा कि वे जांच कर रहे हैं।

अनुजके सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनके एक अतिथि फ्लोरिडा से आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि उन्होंने फेमा कानून का उल्लंघन किया है। उन्हें रोकने वाले ने कहा कि वे अपने साथ तय रकम से अधिक अमेरिकी डॉलर लेकर पहुंचे हैं। अनुज ने पोस्ट में लिखा कि उनसे जितनी रकम की मांग की गई, उसका उन्होंने भुगतान कर दिया लेकिन फिर भी कस्टम ने रोक रखा है। इस पोस्ट पर कस्टम विभाग ने उत्तर देते हुए कहा कि फ्लोरिडा से यहां पहुंचे किसी भी यात्री को कस्टम ने नहीं रोका है। कस्टम विभाग अनुज को ईमेल पर पूरी जानकारी देने को कहा है।

पुलिसवाला बन फ्लैट की तलाशी लेकर विद्यार्थियों से की लूटपाट

हरिनगर थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर के एक फ्लैट में पांच विद्यार्थी किराए पर रहते हैं। यहां एक कार पर सवार होकर चार व्यक्ति फ्लैट पर पहुंचे। चारों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और पांच विद्यार्थी में से एक पर आरोप लगाया कि उसके फ्लैट में गलत काम होता है।

यहां कॉल सेंटर चलाया जाता है और लोगों से ठगी होती है। इसके बाद चारों ने फ्लैट की तलाशी लेनी शुरू कर दी। खुद को पुलिसकर्मी बताने वालों में एक के हाथ में पिस्टल था। आरोप है कि पिस्टल के दम पर शिकायतकर्ता को धमकाया और तलाशी के दौरान ही शिकायतकर्ता व उसके साथियों से 1.55 लाख रुपये लूट लिए।

लूटी गई रकम में से एक लाख रुपये बरामद

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, इंस्पेक्टर मुकेश व प्रताप सिंह की टीम ने इस मामले में छानबीन शुरू की। तकनीकी छानबीन से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मनप्रीत, जुनैद, कुलदीप को दबोचने में कामयाबी पाई।

17 दिनों में पौने तीन करोड़ का हुआ कारोबार

सुषमा रानी

नई दिल्ली। बंपर सेल के साथ संपन्न हुआ स्वाद और संस्कृति का संगम सरस फूड फेस्टिवल। सरस फूड फेस्टिवल ने 17 दिनों में पौने तीन करोड़ का कारोबार किया। तीसरी बार सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। सरस फूड फेस्टिवल ने तीन वर्षों में सबसे अधिक सेल का रिकार्ड बनाया है। एक दिसंबर से सत्रह दिसंबर तक दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) तथा कुडुंबश्री द्वारा समर्थित इस फेस्टिवल में राजधानी के लोगों को भारतीय संस्कृति व खान पान की झलक दिल्ली के हृदय कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में दिखाई दी। समापन समारोह के मौके पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार, अपर सचिव चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा, संयुक्त सचिव अमित शुक्ला, संयुक्त सचिव स्मृति शरण और चिरंजी लाल कटारिया समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

सरस फूड फेस्टिवल के तहत दिल्ली और समीपवर्ती राज्यों के लोग 25 राज्यों की संस्कृति और स्वाद के संगम के संगम से न केवल रूबरू हुए बल्कि इन राज्यों के सामाजिक ताने बाने के बारे में भी जान सके और वहां की प्रसिद्ध व्यंजनों से परिचित हो सके और उसका स्वाद भी चखा। यह राजधानी का एक लोकप्रिय उत्सव है जिसमें न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर के लोग भी विभिन्न राज्यों के व्यंजन चखने और उसे कैसे बनाते हैं यह जानने के लिए आए। फूड फेस्टिवल के दौरान दिल्ली वाले 25 राज्यों के 300 से अधिक उत्कृष्ट व्यंजनों का लुत्फ 30 स्टॉलों पर उठाया।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 01 दिसंबर 2024 से 17 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित हैंडीक्राफ्ट भवन पर सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जिसमें देश भर के 25 राज्यों के क़रीब 150 महिला उद्यमी व स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं 30 से अधिक स्टॉलों पर 300 से अधिक उत्कृष्ट व्यंजनों का दिल्ली वालों को स्वाद का जायका चखाई साथ ही अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित देश भर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं को न केवल ग्रामीण उत्पाद बनाने में कुशलता हासिल है बल्कि विभिन्न राज्यों के परंपरागत पकवान बनाने में उनको दक्षता और महारथ हासिल है।

चांदनी चौक के ऐतिहासिक टाउन हॉल से सभी प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च

सुषमा रानी

नई दिल्ली। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू भाइयों पर हो रहे घोर अत्याचार और बांग्लादेश सरकार के असंवेदनशील रवैये के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (रजि) एवं पुरानी दिल्ली की सभी प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं द्वारा "शांतिपूर्ण विरोध मार्च" का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने "काली पट्टी "बाँध कर भाग लिया और इन दुखद घटनाओं के प्रति अपना रोष प्रकट किया।

यह विरोध मार्च चाँदनी चौक के ऐतिहासिक टाउन हॉल से शुरू हुआ और गौरी शंकर मंदिर पर समाप्त हुआ जिसमें पुरानी दिल्ली की सभी बड़ी छोटी लगभग 140 संस्थाओं के 800 व्यापारियों ने भाग लिया

इस दौरान व्यापारियों ने अपने हाथ में तख्तियां और बैनर ले रखे थे जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की ।इसके पश्चात मंदिर में पूजा-अर्चना करके भगवान से इन कट्टरपंथियों और बांग्लादेश सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई ताकि वहाँ रहने वाले हिंदुओं का नरसंहार अतिशीघ्र बंद हो सके ।साथ ही भारत सरकार से भी अपील की गई कि वो बांग्लादेश सरकार से उच्चतम स्तर पर वार्तालाप स्थापित करे और इन मानवता विरोधी घटनाओं को तुरंत रुकवाए ।

इस अवसर पर जगमोहन गोटेवाला , मुकुंद मिश्रा , हेमंत गुप्ता , राकेश यादव , प्रदीप गुप्ता , नंदकिशोर बंसल , प्रेम अरोड़ा , मुकेश सचदेवा , भगवान बंसल , अजय शर्मा , बलदेव गुप्ता , परमजीत सिंह पम्मा , योगेंद्र चौधरी , राजेंद्र शर्मा , दलीप बिंदल , राजेश शर्मा (बबला) योगेश सिंघल , आशीष ग्रोवर , राजीव गुप्ता , बसंत गुप्ता , मनीष वर्मा , संजय जैन , दीपक मित्तल , ललित अग्रवाल , निरंजन पोद्दार , चंद्रभूषण गुप्ता , राजेंद्र अग्रवाल , आलोक गुप्ता , नरेश गुप्ता , संजय सिंघल , भूपेंद्र सिंह , कमल पलवल , रविंद्र अग्रवाल , सुरेश भार्गव , अभिषेक गनेरीवाला, मैकी जैन , विजेंद्र अग्रवाल , अभिषेक शर्मा , धीरज कौशिक , कमल कालरा , विजय सेठी , राजीव बतरा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ।

बदरपुर विधानसभा सीट से इस बार भिड़ेंगे नए चेहरे, दिलचस्प होगा मुकाबला; जानें अब तक कौन कब जीता

बदरपुर विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा के रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनावी मैदान में नहीं होंगे। आप ने रामसिंह नेताजी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। भाजपा को मजबूत प्रत्याशी उतारना होगा। 1993 में हुए पहले चुनाव में बिधूड़ी ने जनता दल के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी। 1998 में रामसिंह नेताजी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी।

दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की बदरपुर विधानसभा सीट पर पहली बार ऐसा होगा कि यहां भाजपा के कद्दावर नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनावी मैदान में नहीं होंगे। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से बिधूड़ी और आप के राम सिंह नेताजी के बीच ही मुकाबला रहा है।

यहां हुए कुल सात चुनावों में से रामवीर सिंह बिधूड़ी ने चार और रामसिंह नेताजी ने दो बार जीत का स्वाद चखा। इस बार यहां मुकाबला दिलचस्प होने होने जा रहा है। आप ने बदरपुर से रामसिंह नेताजी को प्रत्याशी बनाया है।

जबकि भाजपा की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। यहां से विधायक रहे बिधूड़ी के दक्षिणी दिल्ली सीट से सांसद बनने के बाद भाजपा को मजबूत प्रत्याशी की दरकार होगी।

पिछले विधानसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली की 10 से नौ सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। भाजपा के खाते में बदरपुर सीट आई थी। यहां से रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आप के रामसिंह नेता जी को हराकर बाजी मारी थी।

इस बार परिस्थितियां अलग हो गई हैं। आप ने फिर से रामसिंह नेताजी पर भरोसा जताया है। ऐसे में भाजपा को मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना होगा।

1993 में जनता दल से प्रत्याशी बनकर जीते थे बिधूड़ी

\Bबदरपुर विधानसभा सीट पर 1993 में हुए पहले चुनाव में रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जनता दल के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी। उस समय दूसरे नंबर पर रामसिंह नेताजी रहे थे। वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। भाजपा के प्रत्याशी लज्जा राम तीसरे नंबर पर रहे थे।

1998 में निर्दलीय जीते थे रामसिंह नेताजी

बदरपुर सीट पर 1998 में हुए दूसरे चुनाव में रामसिंह नेताजी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। उन्हें 45.50 फीसदी वोट

मिले थे। दूसरे नंबर पर रामवीर सिंह बिधूड़ी रहे थे। तब वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। भाजपा के सूरजभान तीसरे नंबर पर रहे थे।

2013 में पहली बार भाजपा का खाता खुला

इस सीट पर पहले तीन चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाली भाजपा का खाता पहली बार 2013 में खुला। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रामसिंह नेताजी को हराया था। बिधूड़ी को 34.23 फीसदी वोट मिले थे। जबकि आम आदमी पार्टी नारायण दत्त शर्मा चौथे नंबर पर रहे थे।

डीयू लॉ फैकल्टी की परीक्षा स्थगित, छात्रों के प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय ने लिया फैसला

दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद परीक्षाओं को होल्ड पर कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि कई विषयों का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं लेकिन वह पूरा समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ज्यूडीस प्रूडेंस का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद परीक्षाओं को होल्ड पर कर दिया गया है। अगले चार दिन में विश्वविद्यालय निर्णय लेगा कि परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी। डीयू के विधि संकाय की परीक्षाएं 26 दिसंबर से प्रस्तावित हैं। छात्रों का आरोप है कि कई विषयों का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षक छात्रों को पढ़ रहे हैं लेकिन वह पूरा समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ज्यूडीस प्रूडेंस का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक छात्र ने बताया कि इस कोर्स में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया है। और पहले का पश्चिमी कानून इसमें शामिल है। ऐसे में इसका पाठ्यक्रम बहुत बढ़ गया है। शिक्षक इसे पूरा नहीं करा पाए हैं। इसलिए छात्र मांग कर रहे थे कि जब कक्षाएं देरी से शुरू हुई है तो परीक्षाएं भी देरी से हों। इसके लिए सोमवार को सुबह 10 बजे से छात्र प्रदर्शन पर बैठे थे। शाम को जब विधि संकाय की डीन विभाग से बाहर जाने लगीं तो छात्रों ने उन्हें रोक लिया। और समस्या का निस्तारण करने को कहा। इसके बाद धीरे-धीरे वहां पुलिस बल की संख्या बढ़ती गई। देखते ही छात्र आक्रोशित हो गए हैं। देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा और 100 से अधिक संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी मौके पर तैनात रहे। देर रात विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन बंद किया। एक छात्र ने कहा, दो से तीन दिन का समय दिया गया है।

'जो बांग्लादेशियों को अपना बताएगा उनका कराएंगे डीएनए टेस्ट, डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने उठाए अहम मुद्दे

परिवहन विशेष न्यूज

डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने साहिबाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है और बांग्लादेश से लगातार हो रहे घुसपैठ को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता और पांच करोड़ बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग की।

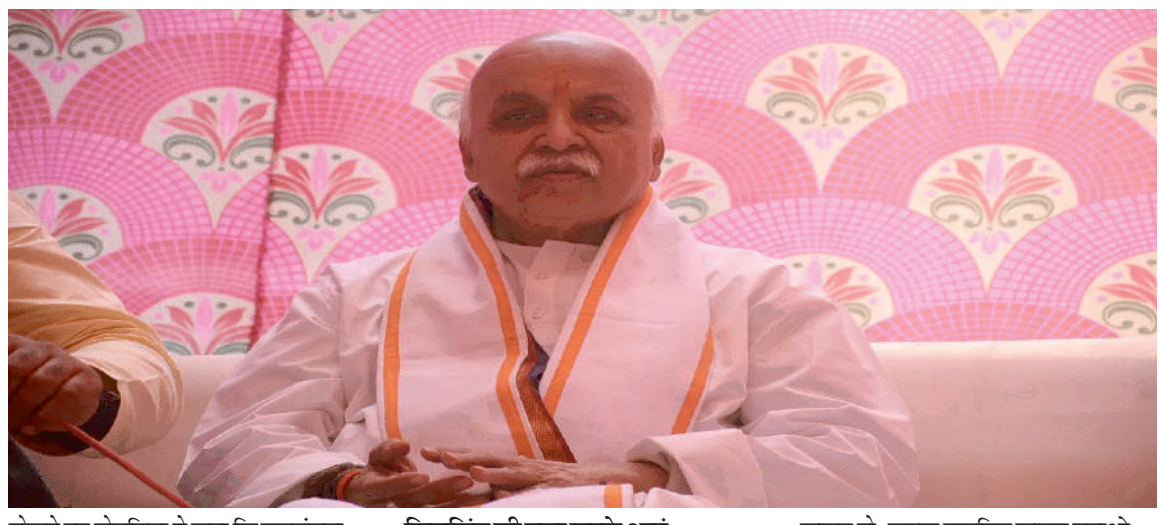

साहिबाबाद (गाजियाबाद)। पहले बांग्लादेश में 28 प्रतिशत हिन्दू थे। अत्याचार के कारण लगातार पलायन के चलते केवल आठ प्रतिशत हिन्दू बचे हैं। वहां हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

जब इजरायल जैसा 90 लाख की आबादी वाला देश यहूदियों की रक्षा के लिए ईरान, फिलिस्तीन, लेबनन, सीरिया, यमन में मार रहा है। मैं इसी भारत का सपना देख रहा हूं। अब यहां से पांच करोड़ बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम मिलकर करेंगे। जो भी उन्हें अपना बताएगा उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे। ये बातें अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के अध्यक्ष डा. प्रवीण तोगड़िया ने एक कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र नगर सेक्टर दो व लाजपत नगर की शिव शक्ति विहार में कहीं।

हिन्दुओं का बहुमत कानून लाना होगा

भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या पर बोलते हुए तोगड़िया ने कहा कि जनसंख्या लगातार घट रही है। आजादी के समय 86 प्रतिशत हिन्दू थे। अब केवल 71 प्रतिशत बचे हैं। वृद्धि दर भी दो से नीचे आ गई है। अगले 70-80 वर्षों में हिन्दुओं की गंभीर स्थिति बनेगी। हर कीमत पर हिन्दुओं का बहुमत कानून लाना होगा।

गांव में कराएंगे हनुमान चालीसा

इसके लिए जनसंख्या भी बढ़ानी होगी। हम कटेंगे तो घटेंगे इसीलिए कम से कम तीन बच्चे पैदा करने होंगे। साथ ही हिन्दुओं को हिन्दुत्व से जोड़ने के लिए हर गांव में मंगल या शनिवार को हनुमान चालीसा भी करा रहे हैं। पहले फेज में एक लाख गांव में हनुमान चालीसा कराएंगे।

विपक्षी दल के नेता संभल जाएं और शिवलिंग की पूजा करके आएं

संभल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला हमारी सरकार पर हमला है। पुलिस पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक केवल मस्जिद में शिवलिंग मिलता था अब घरों के अंदर भी मिलने लगा है। जहां शिवलिंग है वहां हम पूजा करेंगे ही। वहीं, विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वह भी संभल जाएं और शिवलिंग की पूजा करके आएं।

योगी का बुलडोजर शांति का प्रतीक

उन्होंने कहा कि हिन्दुओं को बचाने के लिए आर्थिक शस्त्र के साथ ही ताकत का सहारा भी लेना पड़ेगा। बुलडोजर भी शांति का प्रतीक है। इसके लिए तीन मुद्दे सरकार के सामने रखने पड़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, समान नागरिक कानून बनाओ, पांच करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ।

मोदी-योगी-तोगड़िया की भाषा

तोगड़िया ने संभल के मसले पर कहा कि यहां अब मोदी-योगी-तोगड़िया की भाषा एक है। योगी आदित्यनाथ का शासन है। हम सब उनके साथ हैं। तभी तो वर्षों से बंद मंदिर के दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं। बोले कि पीएम नरेंद्र मोदी से दूरियां खत्म हो गई हैं। संघ से भी मेलमिलाप पहले से है और रहेगा भी।

अन्नदान ही महादान है

उन्होंने कहा कि हम महाकुंभ मेला में श्रद्धालु दूर-दराज से पहुंचेंगे। तीर्थ यात्रियों को भोजन कराना हमारे जीवन का सर्वोत्तम काम है। सभी लोग इसके लिए दान करें।

दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉड में कक्षाएं; NCR के इस शहर में सख्ती से ग्रेप-4 लागू करने के निर्देश

गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में इन दिनों वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए डीसी अजय कुमार ने GRAP 4 लागू कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव प्राइवेट संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम स्कूलों में हाइब्रिड मॉड में कक्षाएं निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक सहित कई पाबंदियां लगाई गई हैं।

गुरुग्राम। डीसी अजय कुमार ने सोमवार देर रात दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू होने के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रेप 4 की पाबंदियां सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

डीसी द्वारा जारी आदेशों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है। आदेशों के तहत अब सभी सरकारी कार्यालय में कर्मचारी सुबह 9.30 बजे दफ्तर आएंगे व शाम 5.30 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे।

ग्रेप 4 की पाबंदियों का सख्ती से हो पालन

वहीं सभी नगर निकायों में कमर्चारियों के ऑफिस आने का समय प्रातः 8.30 बजे व वापिस जाने का समय शाम 4.30 बजे निर्धारित किया गया है। एयर क्वालिटी में सुधार के दृष्टिगत डीसी ने सभी प्राइवेट संस्थानों में अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की एडवाइजरी जारी की है।

वहीं ग्रेप 4 की पाबंदियों की पालना के तहत सभी स्कूलों में 10वीं व 12वीं कक्षाओं को छोड़कर हाइब्रिड मॉड में कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए। डीसी ने सीएक्यूएम द्वारा एनसीआर क्षेत्र में नागरिकों के लिए जारी की गई।

एडवाइजरी का हवाला देते हुए आग्रह किया कि बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। अगर किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है तो मास्क जरूर पहनें।

इन कामों पर भी लगी रोक

बता दें कि ग्रेप 4 की पाबंदियों के तहत जिला में राजमार्ग व फ्लाईओवर समेत सार्वजनिक व निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी। कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी, पॉलीथीन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

चार बिंदुओं में समझें:

कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक।

खुले में कचरा जलाने पर रोक।

पॉलीथीन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग पर रोक।

वहीं बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई।

वहीं बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सीमेंट, ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण पर पाबंदी रहेगी।

मुरादनगर में गंगनहर के पास मिला सूटकेस, खुलते ही पुलिस के उड़े होश; शहर में हड़कंप

गाजियाबाद के मोदीनगर में गंग नहर पटरी के किनारे एक सूटकेस में बंद बच्चे का शव मिला है। बच्चे की उम्र करीब 5-6 साल है और उसके हाथ पर प्लास्टर भी बंधा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर फेंका गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

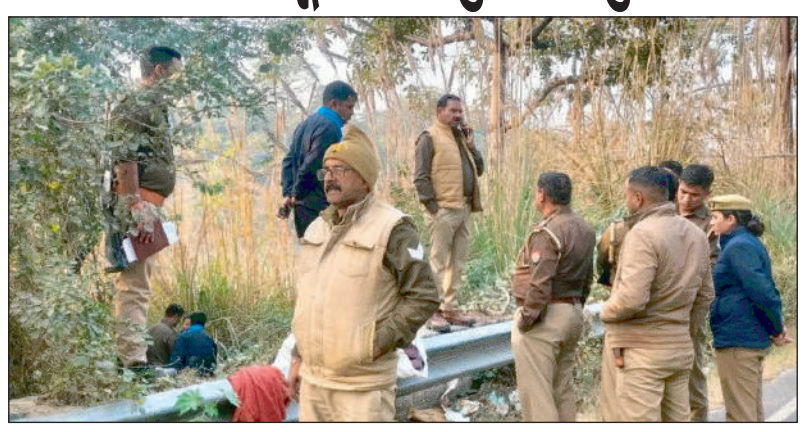

मोदीनगर (गाजियाबाद)। शहर के निवाड़ी थाना क्षेत्र में गंग नहर पटरी के किनारे पुलिस चौकी से करीब 400 मीटर की दूरी पर सूटकेस में बंद एक बच्चे का शव मिला। बच्चे की आयु की पांच से छह वर्ष के बीच बताई जा रही है।

बच्चे के हाथ पर प्लास्टर भी बंधा हुआ। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चे की हत्या करके शव को पटरी मार्ग पर फेंका गया है। हत्यारा सूटकेस को नहर में फेंकना था, किंतु वह झाड़ियों में फंस गया।

बच्चे का शव मिलने की खबर फैलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। शव की पहचान नहीं हो सकी है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर उसके बारे में अन्य क्षेत्र में भेज दी है।

पुलिस को सूटकेस मिलने की दी गई सूचना

मंगलवार दोपहर को करीब दो बजे कुछ राहगीरों ने मुरादनगर में गंगनहर पुलिस चौकी पर सूचना दी कि गंगनहर पटरी मार्ग पर एक सूटकेस संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ है, जिसके आसपास आवारा पशु घूम रहे हैं। सूटकेस की खुली हुई चेन में एक हाथ भी बाहर निकला हुआ है।

इस बारे में मुरादनगर पुलिस द्वारा सूचना भेजे जाने पर पर निवाड़ी के थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर जाकर सूटकेस को देखा तो उसमें से एक बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे की आयु पांच से छह वर्ष के बीच है और उसने लाल रंग का स्वेटर व काले रंग की लोवर पहनी हुई।

बच्चे द्वारा पहने हुए कपड़े किसी स्कूल की ड्रैस के लग रहे हैं। बच्चे के बायें हाथ पर एक प्लास्टर भी बंधा हुआ है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी ने अपहरण करके बच्चे की हत्या की ओर शव को सूटकेस में बंद करने के बाद पटरी मार्ग पर फेंक गया।

पुलिस टीम ने खोजी कुत्तों की सहायता से आसपास के क्षेत्र में सूत्रों की तलाश की। बाद में फारेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाये। पुलिस टीम ने बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने बच्चे के संबंध में आसपास के क्षेत्र में सूचना भिजवा दी है। डीसीपी एसएन तिवारी भी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटी पुलिस टीम को जरूरी निर्देश दिए।

पुलिस गश्त की खुली कलई

बच्चे के शव वाला सूटकेस पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर मिलने के कारण गंगनहर पर लगातार गश्त के पुलिस द्वारा किए गए दावों की कलई खुल गई है। रात में पटरी पर सफर करने वाले लोगों का कहना है कि महत्वपूर्ण स्थानों पर से पुलिसकर्मी नदारद ही मिलते हैं।

सूटकेस को नहर में फेंकने का था इरादा

जिस प्रकार सूटकेस झाड़ियों में अटका हुआ मिला, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्यारे की मंशा उसे नहर में फेंकने थी, लेकिन सूटकेस बीच में ही फंस गया।

बच्चे का शव मिलने की खबर मिलने पर लोगों ने व्यक्त की संवेदना

पटरी मार्ग पर बच्चे का शव मिलने की खबर कुछ ही देर में आसपास के क्षेत्र में फैल गई। बच्चे के शव के बारे में पता चलने पर लोगों ने मौखिक संवेदनाएं प्रकट की और उसके हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होने की उम्मीद जताई।

इसके अलावा बच्चे का मिलने से संबंधित जानकारी इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित होती रही। दो वर्ष पूर्व भी गंगनहर के किनारे से छह वर्षीय बच्ची का शव मिला था। जिसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके फेंका गया था।

एसीपी ज्ञानप्रकाश राय का कहना है कि बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा। पुलिस टीम बच्चे की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी हुई है।

रैपर बादशाह को भारी पड़ी लापरवाही

ट्रैफिक पुलिस ने काटा 15 हजार का चालान

सिंगर और रैपर बादशाह को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 15 हजार रुपये का चालान काटा है। उन पर सड़क की गलत साइड पर गाड़ी चलाने तेज आवाज में गाना बजाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। वह गुरुग्राम में एक पंजाबी सिंगर के कॉन्सर्ट में आए थे।

गुरुग्राम। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने रैपर और सिंगर बादशाह पर 15,000 रुपये का चालान काटा है। उन पर सड़क की गलत साइड पर गाड़ी चलाने, तेज आवाज में गाना बजाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना 15 दिसंबर की है। सिंगर और रैपर बादशाह पंजाबी गायक करण औजला के एक कॉन्सर्ट में शामिल होने आए थे, यह कार्यक्रम सोहाना रोड स्थित ऐरिया मॉल में था।

ट्रैफिक में से निकल गलत साइड पर पहुंची कार : बादशाह जिस कार में मौजूद थे, वह महिंद्रा थार थी। यह कार पानीपत के रहने वाले दीपेंद्र मलिक के राम पर रजिस्टर्ड है। लंबा ट्रैफिक होने के कारण, बादशाह के काफिले में शामिल एसयूवी सड़क की गलत साइड पर चली गई। इस दौरान पर मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी।

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। पुलिस ने सोमवार को रैपर के खिलाफ 15 हजार रुपये का चालान जारी किया।

पुलिस ने क्या कहा : यातायात निरीक्षक (ट्रैफिक इंस्पेक्टर) देवेन्द्र कुमार ने बताया कि तेजी से वाहन चलाने, वाहन में तेज आवाज में गाना बजाने और गलत दिशा में वाहन चलाने के लिए चालान जारी किया गया है और कार्रवाई की गई है।

महान तबला वादक जाकिर हुसैन का दुनियाँ को अलविदा -पीढ़ियां इस बात पर गर्व करेगी कि ऐसा पुष्प हिंद के आंगन में उगा था

पूरी दुनियाँ उस्ताद जाकिर हुसैन की तबला थापों के संगीत की खुशबू से महकती है

उस्ताद जाकिर हुसैन से प्रेरित होकर मैंने भी संगीत (तबला) वादन में 5 वर्षीय संगीत माध्यमा किया अब विशारद शीघ्र पूर्ण करूंगा- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर संगीत क्षेत्र में आज भी आश्चर्य होता है कि क्या सुर सम्राट तानसेन भारत में ही पैदा हुए थे? उसी प्रकार ही आगे के दौर में हमारी पीढ़ियां इस बात पर गर्व करेगी कि हिंद के आंगन में ऐसे पुष्प भी उगे थे।तबला वादक उस्ताद हमारे वतन के थे, जिनकी कमी को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। मैं खुद भी उनका फैन रहा हूं व उनके तबला वादन की कला से प्रेरित होकर मैं भी संगीत सीखने व तबला वादन में 9 वर्षीय कोर्स अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मुंबई से करने की ठानी व 5 वर्ष तक संगीत माध्यम (तबला) वादन में सफलता पूर्वक पूर्ण किया जिसमें रिटर्न ओरल व प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती है जो मैंने सफलतापूर्वक पास की व संगीत माध्यमा बना, परंतु कुछ व्यस्तता के कारण बाकी के दो वर्ष विशारद अधूरे रह गए हैं जिसे पूर्ण करने का संकल्प मेरे मन में है। आज हम उस्ताद जाकिर हुसैन की नम आंखों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दिनांक 16 दिसंबर 2024 को तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। यहां उनका इलाज चल रहा था।उनके परिवार ने सोमवार को उनके निधन की पुष्टि की जो पिछले दो हफ्ते से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भरती थे। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग के इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, महान तबला वादक जाकिर हुसैन का दुनियाँ को अलविदा, पीढ़ियां इस बात पर गर्व करेगी कि ऐसाअनमोल पुरुष हिंद के आंगन में उगा था।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तरपर मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन की करें तो, सोमवार सुबह परिवार ने जाकिर हुसैन के निधन की पुष्टि कर दी है परिवार ने खुलासा किया कि उनकी मृत्यु इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से हुई, जो फेफड़ों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। मीडिया के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस लेने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को में ही सुपुर्द-ए खाक़ किया जाएगा और उन्हें भारत नहीं लाया जाएगा। मीडिया में बताया कि जाकिर हुसैन को संभवतः बुधवार के दिन सैन फ्रांसिस्को में दफन किया जाएगा। जाकिर हुसैन के भाई फ़ज़ल कुरैशी भारत से अमेरिका पहुंच गये हैं और बहन खुर्शीद औलिया भी लंदन से अमेरिका पहुंच गई है।

साथियों बात अगर हम उस्ताद के बारे में जानने की करें तो ज़ाकिर हुसैन बेहद मशहूर तबला वादक थे।उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई थी।1951 में उस्ताद अल्लाह रक्खा के घर जन्मे जाकिर बचपन से ही बेहद टैलेंटेड थे, उन्होंने सात साल की उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था।जाकिर हुसैन न सिर्फ एक महान तबला वादक थे बल्कि एक बेहतरीन संगीतकार भी थे, उन्होंने हीट एंड डस्ट और इन कस्टडी जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक भी दिया था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैले और आर्केस्ट्रा प्रोडक्शन के लिए कुछ मैजिकल कंपोजिशन भी बनाई थीं। जाकिर हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला उनकी बेटियां अनीसा कुरैशी (उनके पति टेलर फिलिप्स और उनकी बेटी जारा) और इसाबेला कुरैशी, उनके भाई तौक कुरैशी और फजल कुरैशी व उनकी बहन खुर्शीद औलिया हैं। साथियों बात अगर हम उस्ताद पर पुरस्कारों सम्मानों की बारिश की करें तो, पद्मश्री से लेकर पद्मविभूषण से किये गये थे सम्मानितजाकिर हुसैन को कई अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था, उन्हें साल 1988 में पद्मश्री से नवाजा गया था. इसके बाद साल 2002 में उन्हें पद्मभूषण और साल 2023 में पद्मविभूषण जैसे सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. हुसैन को 1990 में संगीत के सर्वोच्च सम्मान 'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' से भी नवाजा गया था 4 बार ग्रैमी पुरस्कार से हुए थे सम्मानितबता दें कि जाकिर हुसैन को कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूज़िक एलबम कैटगरी में 'ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट' एल्बम के लिए 2009 में 51वें ग्रैमी अवॉर्ड्स से नवाज़ा गया था. गौरतलब है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को अपने करियर में 7 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था जिनमें से उन्हें चार बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

साथियों बात अगर हम उस्ताद के निधन पर आम आदमी से देखकर पीएम,विपक्षी नेता सहित राजनीतिक बॉलीवुड व अन्य क्षेत्र के सामान्य व्यक्तियों द्वारा दुखी होकर संवेदनाएं प्रकट करने की करें तो दुखी होने की करें तो, प्रधानमंत्री ने एक्स पर ज़ाकिर हुसैन को याद करते हुए पोस्ट किया है, कि ज़ाकिर हुसैन को भारतीयशास्त्रीय संगीत की दुनिया में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता रहेगा.

साथियों बात अगर हम उस्ताद के निधन पर आम आदमी से देखकर पीएम,विपक्षी नेता सहित राजनीतिक बॉलीवुड व अन्य क्षेत्र के सामान्य व्यक्तियों द्वारा दुखी होकर संवेदनाएं प्रकट करने की करें तो दुखी होने की करें तो, प्रधानमंत्री ने एक्स पर ज़ाकिर हुसैन को याद करते हुए पोस्ट किया है, कि ज़ाकिर हुसैन को भारतीयशास्त्रीय संगीत की दुनिया में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता रहेगा.हुसैन को जीनियस बताते हुए लिखा, वे तबले को ग्लोबल स्टेज तक ले गए, उन्होंने भारत की शास्त्रीय परंपराओं को ग्लोबल म्यूज़िक से मिलाया और इसलिए वो सांस्कृतिक एकता के आइकन बन गएजावेद अख़्तर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि संगीत की दुनिया ने एक 'ताल' खो दिया है।जावेद अख़्तर ने लिखा है,एक महान संगीतकार, एक महान इंसान, एक अच्छे मित्र ज़ाकिर हुसैन साहब हमें छोड़कर चले गए.नेताओं ने सोशल मीडिया पर जताया दुखलोकसभा में विपक्ष के नेता ने पोस्ट किया,महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। उनका निधन संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और फैंस के साथ हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जी अपनी कला की ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगी।' असम के सीएम ने भी एक्स पर दुख जताया। संचार मंत्री और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया।

साथियों बात अगर हम उस्ताद क़े आईपीएफ बीमारी से ग्रस्त होकर निधन होने की करें तो,इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (आईपीएफ) क्या है? इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में छोटी-छोटी हवा की थैलियों से होते हुए खून में जाता है और फिर यहां से शरीर के सभी अंगों को मिलता है। लेकिनआईपीएफ होने पर फेफड़ों के भीतर निशान ऊतक बढ़ने लगते हैं। जिससे सांस लेना मुश्किल होने लगता है। उम्र के साथ ये समस्या और भी खराब होने लगती है। इससे फेफड़ों के जरिए खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जिससे आपके शरीर के दूसरे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं।इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लक्षण और इलाज,,आपको बता दें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का कोई इलाज नहीं है इस सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। स्थिति गंभीर होने पर लंग ट्रांसप्लांट का विकल्प होता है। धीरे धीरे फेफड़ों में ऊतक बढ़ने लगते हैं और फेफड़ों में जख्म जैसे हो जाके हैं। जिसकी वजह से आपको सीने में दर्द या जकड़न, पैर में सूजन, भूख में कमी, गले में खराश, खांसी, थकान महसूस होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, वजन घटना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर आप किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं तो मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पुरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि महान तबला वादक जाकिरहुसैन का दुनियाँ को अलविदा -पीढ़ियां इस बात पर गर्व करेगी कि ऐसा पुष्प हिंद के आंगन में उगा था।पूरी दुनियाँ उस्ताद जाकिर हुसैन की तबला थापों के संगीत की खुशबू से महकती है।उस्ताद जाकिर हुसैन से प्रेरित होकर मैंने भी संगीत (तबला) वादन में 5 वर्षीय संगीत माध्यमा किया अब विशारद शीघ्र पूर्ण करूंगा

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

लेम्बोर्गिनी ने पहली इलेक्ट्रिक कार की लॉन्चिंग 2029 तक टाली

परिवहन विशेष न्यूज

(रायटर) - इटली की लेम्बोर्गिनी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन विंकेलमैन ने सोमवार, 16 दिसंबर को कहा कि कंपनी वर्ष 2029 में अपना पहला इलेक्ट्रिक मॉडल लांच करने की योजना बना रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स कार बाजार खंड में पूर्ण विद्युतीकरण के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है।

लेम्बोर्गिनी, वोक्सवैगन की एक इकाई ने पहले कहा था कि उसका पहला ईवी 2028 में आने वाला है। इतालवी लेम्बोर्गिनी की प्रतिद्वंद्वी फेरारी अगले वर्ष की अंतिम तिमाही में अपना पहला ईवी मॉडल लॉन्च करेगी।

विंकेलमैन ने उत्तरी इतालवी शहर बोलोग्ना के पास, सैंट अगाटा बोलोग्नीस में लेम्बोर्गिनी के मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, रहमें नहीं लगता कि 2029 तक इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध हो जाएगी। हमारे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार 2025 या 2026 तक तैयार हो जाएगा।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए दिन और रात के लिए अलग-अलग टैरिफ होंगे

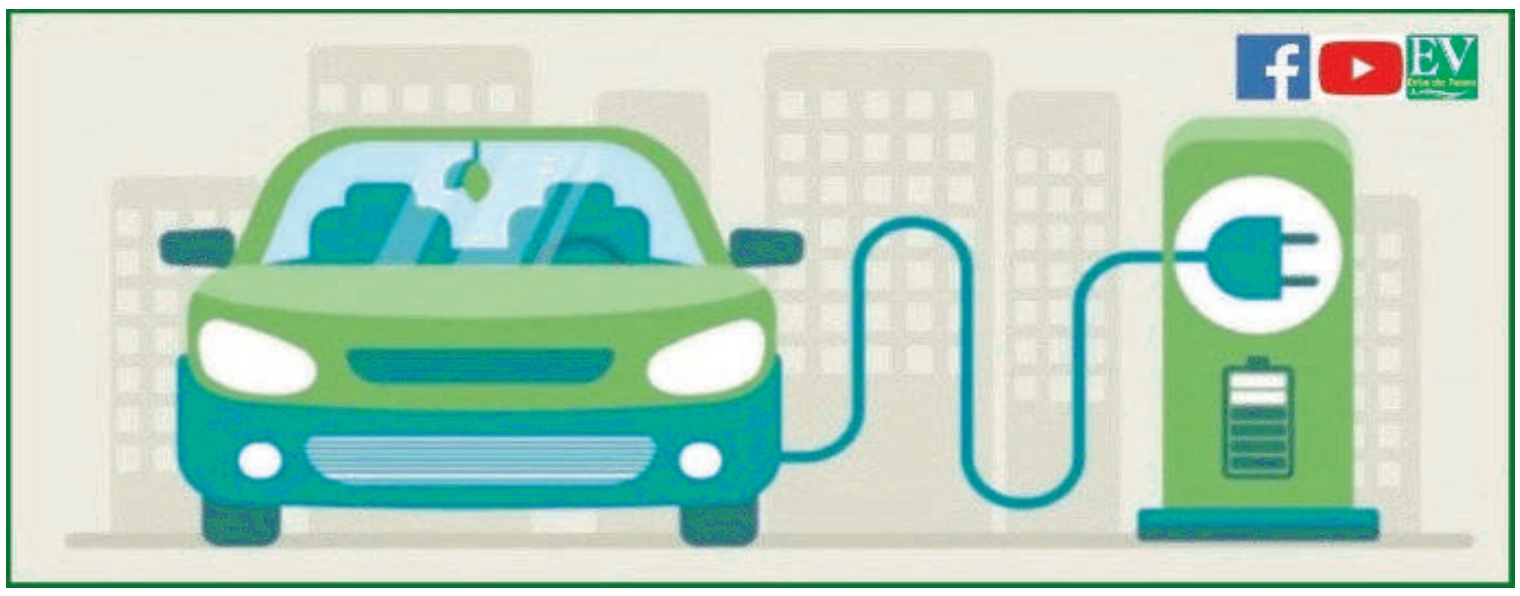

परिवहन विशेष न्यूज

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसे झारखंड समेत अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजकर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। नई गाइडलाइन में चार्जिंग स्टेशनों को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य एक मजबूत राष्ट्रीय चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना भी है।

इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं को निजी ऑपरेटरों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। बदले में जमीन के मालिकाना हक वाली एजेंसी को 10 साल की अवधि के लिए चार्जिंग स्टेशन पर खपत की गई बिजली के आधार पर राजस्व का हिस्सा दिया जाएगा।

ईवी चार्जिंग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, चार्जिंग स्टेशनों में दिन और रात के लिए अलग-अलग टैरिफ रखने का प्रावधान है। चार्जिंग स्टेशनों पर बिजली की लागत को न्यूनतम रखने का प्रावधान किया गया है, खासकर सौर ऊर्जा घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान। इसमें कहा गया है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक एसी (धीमी) की दर 3 रुपये प्रति यूनिट, शाम 4 बजे से सुबह 9 बजे तक 4 रुपये प्रति यूनिट और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डीसी (तेज) की दर 11 रुपये प्रति यूनिट और बाकी समय में 13 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है।

चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली कनेक्शन की अवधि भी तय की गई है। सभी राज्यों को एक नोडल एजेंसी बनाने को कहा गया है ताकि बिजली वितरण और चार्जिंग स्टेशनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राजमार्गों के किनारे नियमित ईवी चार्जिंग के लिए हर 20 किलोमीटर और बसों और ट्रकों जैसे लंबी दूरी और भारी वाहनों के लिए हर 100 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बड़े चार्जिंग स्टेशनों को ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए वॉशरूम, पीने का पानी और निगरानी जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

ईवी के टॉप 5 में कौन और सबसे कम मांग वाला राज्य

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी है कि अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के बीच पांच सालों में कितने इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि इस दौरान देश के किस राज्य में कितने इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान देशभर में कुल 36,39,617 यूनिट ईवी की बिक्री हुई है।

बिक्री के मामले में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा ईवी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनमें यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के बीच 6,65,247 यूनिट ईवी रजिस्टर हुए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां 4,39,358 यूनिट ईवी रजिस्टर हुए हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां 3,50,810 यूनिट रजिस्टर हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर है जहां 2,28,850 यूनिट्स रजिस्टर हुई हैं। राजस्थान 2,33,503 यूनिट्स रजिस्टर्ड के साथ टॉप 5 लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। दिल्ली इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है। इस दौरान दिल्ली में कुल 2,1,6084 यूनिट्स रजिस्टर हुई हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, सिक्किम में 2019 से 2024 के बीच एक भी इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर नहीं हुआ है। इसके अलावा लक्षद्वीप में 19, नागालैंड में 27, अरुणाचल प्रदेश में 42, लद्दाख में 88, अंडमान निकोबार में 191, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 468, मिजोरम में 344, मेघालय में 572, मणिपुर में 1273, हिमाचल प्रदेश में 3043 और पुडुचेरी में 5933 यूनिट्स रजिस्टर हुई हैं।

सेकेंड हैंड छोटी और ईवी कारें हो सकती महंगी, GST की दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने का विचार

परिवहन विशेष न्यूज

आगे चलकर पेट्रोल डीजल से चलने वाली सेकेंड हैंड छोटी एवं इलेक्ट्रिक कारों की कीमत के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। पुरानी छोटी कार व पुरानी इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर जीएसटी की वर्तमान 12 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। चार मीटर से अधिक लंबाई वाली सेकेंड हैंड कार की बिक्री पर पहले से ही 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

नई दिल्ली। पेट्रोल डीजल से चलने वाली सेकेंड हैंड छोटी एवं इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी के लिए भविष्य में वर्तमान की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जीएसटी दरों से जुड़ी फिटमेंट कमेटी ने सेकेंड हैंड छोटी व इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर जीएसटी की दर बढ़ाने की सिफारिश की है। आगामी 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस सिफारिश पर फैसला किया जा सकता है।

छोटी कार व पुरानी इलेक्ट्रिक कार

सूत्रों के मुताबिक फिटमेंट कमेटी ने पुरानी छोटी कार व पुरानी इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर जीएसटी की वर्तमान 12 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। सेकेंड हैंड कार के सप्लायर के मार्जिन पर जीएसटी वसूला जाता है। जीएसटी दर अधिक होने पर सप्लायर सेकेंड हैंड छोटी कार की कीमत बढ़ा देगा। चार मीटर से अधिक लंबाई वाली सेकेंड हैंड कार की बिक्री पर पहले से ही 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर असर

फिटमेंट कमेटी की सिफारिश पर अमल करने से इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर असर पड़ सकता है। सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी को लेकर ग्राहक पहले से ही उदासीन है और अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो बिक्री और प्रभावित हो जाएगी। पुरानी इलेक्ट्रिक कार को बेचने में होने वाली परेशानी की वजह से भी इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी के प्रति लोगों में अभी आकर्षण कम है। नई इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है।

20 दिसंबर को लॉन्च होगा नया बजाब चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, नए बैटरी पैक समेत मिलेगा ज्यादा रेंज

परिवहन विशेष न्यूज

नया बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर 20 दिसंबर 2024 को भारत में लॉन्च होने वाला है। इसके लॉन्च होने से पहले टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। जिसमें इसका नया डिजाइन देखने के लिए मिला है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नए चेतक में मौजूदा से बेहतर बैटरी पैक मिलेगा जो ज्यादा रेंज कैपेसिटी के साथ आएगा।

नई दिल्ली। बजाज ऑटो जल्द ही अपनी नई चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसकी टेस्टिंग भी कर रही है। इसे नई बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर 20 दिसंबर, 2024 को लॉन्च होगा। हाल ही में इसके टेस्टिंग मॉडल को स्पॉट किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसके नए डिजाइन को देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इसे नए कलर ऑप्शन के साथ भी पेश किया जा सकता है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। आइए जानते हैं कि नए Bajaj Chetak Electric Scooter के टेस्टिंग मॉडल में क्या देखने के लिए मिला है।

New Bajaj Chetak Electric Scooter: क्या मिलेगा नया

नई बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें कई सुधार दिख सकते हैं। नए चेतक में फ्लोरबोर्ड एरिया के नीचे बैटरी के साथ एक नई चेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी वजह से इसमें पहले से ज्यादा बूट स्पेस मिल सकता है। साथ ही बड़े अंडरसीट स्टोरेज भी मिल सकता है। हाल में चेतक में 21 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी दी जाती है।

ऑटो एक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग म्यूल में स्टील के पहिये और दोनों छोर पर ड्रम ब्रेक भी देखने के लिए मिले हैं। हालांकि, इसमें लॉक करने योग्य ग्लव बॉक्स नहीं देखने के लिए मिले हैं, जो मौजूदा मॉडल में इसके फ्रंट एप्रन के पीछे दिए गए हैं। इसमें कीलेस इग्निशन सिस्टम भी देखने के लिए नहीं मिला है। वहीं, स्कूटर में दाईं ओर एक अधिक पारंपरिक और भौतिक कुंजी स्लॉट देखने के लिए मिली है।

New Bajaj Chetak Electric Scooter: बैटरी और रेंज

नई बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में नया बैटरी पैक देखने के लिए मिल सकता है, जो संभावित रूप से इसकी रेंज बढ़ा सकता है। इसके साथ ही मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा कैपेसिटी के साथ आ सकती है। ऑटो एक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 123 किमी से 137 किमी के बीच की रेंज दे सकती है। इसके नए वर्जन में स्कूटर की रेंज को बढ़ाने की उम्मीद है, जिसकी वजह से लंबी दूरी तक का सफर इलेक्ट्रिक स्कूटर से किया जा सकें।

New Bajaj Chetak Electric Scooter: कीमत

नई बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत मौजूदा से ज्यादा हो सकती है। हाल में बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध बजाज चेतक की कीमत 95,998 रुपये से शुरू होकर 1.29 लाख रुपये तक जाती है।

मारुति ग्रेंड विटारा की 7-सीटर टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, ई-विटारा जैसा दिखा डिजाइन

परिवहन विशेष न्यूज

हाल ही में मारुति सुजुकी की एक 7-सीटर SUV को भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इसे 7-सीटर SUV को नई Maruti Grand Vitara कहा जा रहा है। जिसकी पीछे की वजह साल 2023 में कंपनी के जरिए कही गई बात है। इस समय कंपनी ने कहा गया था कि वह 7-सीटर ग्रैंड विटारा पर काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय सड़कों पर ऑटोमेकर मारुति की नई SUV को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इसे मारुति ग्रैड विटारा की तीन पंक्ति वाला वेरिएंट कहा जा रहा है। वहीं, कंपनी की तरफ से भी साल 2023 में कहा गया था कि वह ग्रैंड विटारा के 7-सीटर वेरिएंट पर काम कर रही है। वहीं, भारत की सड़कों पर इसके पहले प्रोटोटाइप की झलक देखने के लिए मिली है। आइए जानते हैं कि यह किन फीचर्स के साथ आने वाली है।

Maruti Grand Vitara: पहली बार में क्या दिखा

ऑटोकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हूई Grand Vitara के दरवाजों को देखकर इसके SUV का होने का पता चलता है। इसमें विंडो लाइन और यहाँ तक कि मिरर की स्थिति भी नियमित ग्रैंड विटारा से काफी मिलती-जुलती है। वहीं, जब इसे पास से देखा गया तो इसकी तीसरी पंक्ति भी देखने के लिए मिली है। जिसमें पीछे की तरफ थोड़ा लंबा ओवर हैंग दिखाई देता है। इसका व्हीलबेस भी देखने के लिए पहले के मुताबिक बढ़ा हुई दिखता है।

वहीं, देखने में Grand Vitara 7-सीटर के लाइटिंग और फ्रंट बम्पर आगामी मारुति ई-विटारा से प्रेरित लगते हैं। इसके ऊपर की तरफ एक एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट सेटअप देखने के लिए मिलता है। इसमें मारुति के सिग्नेचर थ्री-डॉट मोटिफ है, जबकि मुख्य हेडलैम्प बम्पर पर दिखाई दिए हैं। सेंट्रली माउंटेड एयर इनलेट के साथ बम्पर की सरफेसिंग भी ई विटारा के जैसी ही दिखने में लगते हैं। इसके पीछे की तरफ रैप अराउंड फुल-चौड़ाई वाले एलईडी टेल-लैंप भी देखने के लिए मिला है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसका डैशबोर्ड पूरी तरह से नए डिजाइन में देखने के लिए मिला है, इसके साथ ही फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने के लिए मिला है।

Maruti Grand Vitara: इंजन प्लेटफॉर्म

7 सीटर ग्रैंड विटारा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन देखने के लिए मिल सकता है। इसके इंजन के साथ कई गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। ऑटोकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 7-सीटर ग्रैंड विटारा को हरियाणा के खरखौदा में मारुति के आगामी प्लांट में बनाया जाएगा। यह नया प्लांट साल 2025 के मध्य से चालू किया जाएगा। संभवतः इस प्लांट में बनी हुई पहली गाड़ी भी हो सकती है। ग्रैंड विटारा 7-सीटर को साल 2025 के आखिरी में लॉन्च किया जा सकता है।

आईआईटी मद्रास के पास एक डिजिटल मानव मस्तिष्क एटलस तैयार है

विजय गर्ग

अनुमान है कि मस्तिष्क लगभग 80 अरब न्यूरॉन्स से बना है, जिसमें खरबों कनेक्शन समझ से परे जटिलता का एक नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क का मानचित्रण करना लंबे समय से तंत्रिका वैज्ञानिकों का एक सपना रहा है, लेकिन मौजूदा उपकरण मस्तिष्क की संरचना कैसे होती है और इसके विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं, इसकी स्पष्ट, विस्तृत तस्वीर प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित है। हालाँकि, आईआईटी मद्रास की टीम इसे बदल रही है।

दुनिया का सबसे विस्तृत डिजिटल मानव मस्तिष्क एटलस बनाकर, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो चिकित्सा और एआई दोनों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल सकती है। मानव मस्तिष्क की जटिलता ने हमेशा विज्ञान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को प्रस्तुत किया है। अल्जाइमर, पार्किंसंस और मिर्गी जैसे तंत्रिका संबंधी विकार दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, फिर भी हम अभी भी उनके अंतर्निहित कारणों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानते हैं। मौजूदा उपचार अक्सर महंगे होते हैं, उन तक पहुंचना कठिन होता है और वे केवल मामूली रूप से प्रभावी होते हैं। इससे लाखों मरीज़ों और परिवारों को भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही देखभाल के बोझ से स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ भी तनावग्रस्त हो गई हैं। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में तेजी से प्रगति उद्योगों को बदल रही है और नए अवसर पैदा कर रही है, फिर भी मानव मस्तिष्क की दक्षता, अनुकूलनशीलता और सीखने की क्षमता की तुलना में एआई अभी भी फीका है। बड़े पैमाने पर डेटासेट को संसाधित करने और अलौकिक गति से विशिष्ट कार्य करने की क्षमता के बावजूद, एआई सिस्टम ऊर्जा-गहन बने हुए हैं और उनमें लचीलेपन की कमी है जो स्वाभाविक रूप से मानव संज्ञान में आती है। यदि हम बेहतर ढंग से समझ सकें कि मस्तिष्क कैसे काम करता है - इसकी अनुकूलनशीलता, दक्षता और जानकारी संसाधित करने की क्षमता - तो हम न केवल न्यूरोलॉजिकल रोगों के उपचार में बल्कि एआई के भविष्य में भी क्रांति ला सकते हैं। यहीं पर आईआईटी मद्रास में किया जा रहा काम सामने आता है। दुनिया का सबसे विस्तृत डिजिटल मानव मस्तिष्क एटलस बनाकर, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो चिकित्सा और एआई दोनों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल सकती है। यह डिजिटल मस्तिष्क एटलस मानव मस्तिष्क को अभूतपूर्व स्तर पर विस्तार से मैप करेगा, इसकी संरचना, कनेक्टिविटी और अंतर्निहित तंत्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जो मानव अनुभूति को इतना अद्वितीय बनाता है। अनुमान है कि मस्तिष्क लगभग 80 अरब न्यूरॉन्स से बना है, जिसमें खरबों कनेक्शन समझ से परे जटिलता का एक नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क का मानचित्रण करना लंबे समय से तंत्रिका वैज्ञानिकों का एक सपना रहा है, लेकिन मौजूदा उपकरण मस्तिष्क की संरचना कैसे होती है और इसके विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं, इसकी स्पष्ट, विस्तृत तस्वीर प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित है। हालाँकि, आईआईटी मद्रास की टीम इसे बदल रही है। उनके प्रोजेक्ट में मानव मस्तिष्क को अति-पतले खंडों में विभाजित करना शामिल है - प्रति मस्तिष्क 10,000 स्लाइस - प्रत्येक को दसियों गीगापिक्सेल रिज़ॉल्यूशन पर कैप्चर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे मस्तिष्क का एक 3डी, पूरी तरह से डिजिटल मॉडल तैयार होता है।

यह प्रक्रिया प्रति मस्तिष्क तीन पेटाबाइट डेटा उत्पन्न करती है, जिससे एक डेटासेट तैयार होता है जो इस सबसे जटिल अंग की आंतरिक कार्यप्रणाली में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक रोमांचक नए विकास में, आईआईटी मद्रास के सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर ने मानव भ्रूण के मस्तिष्क का पहला 3डी उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग डेटासेट धरनी जारी किया है। सेलुलर रिज़ॉल्यूशन पर 5,000 से अधिक अनुभागों की विशेषता वाला यह अभूतपूर्व डेटासेट शोधकर्ताओं को प्रारंभिक मस्तिष्क विकास का एक विस्तृत

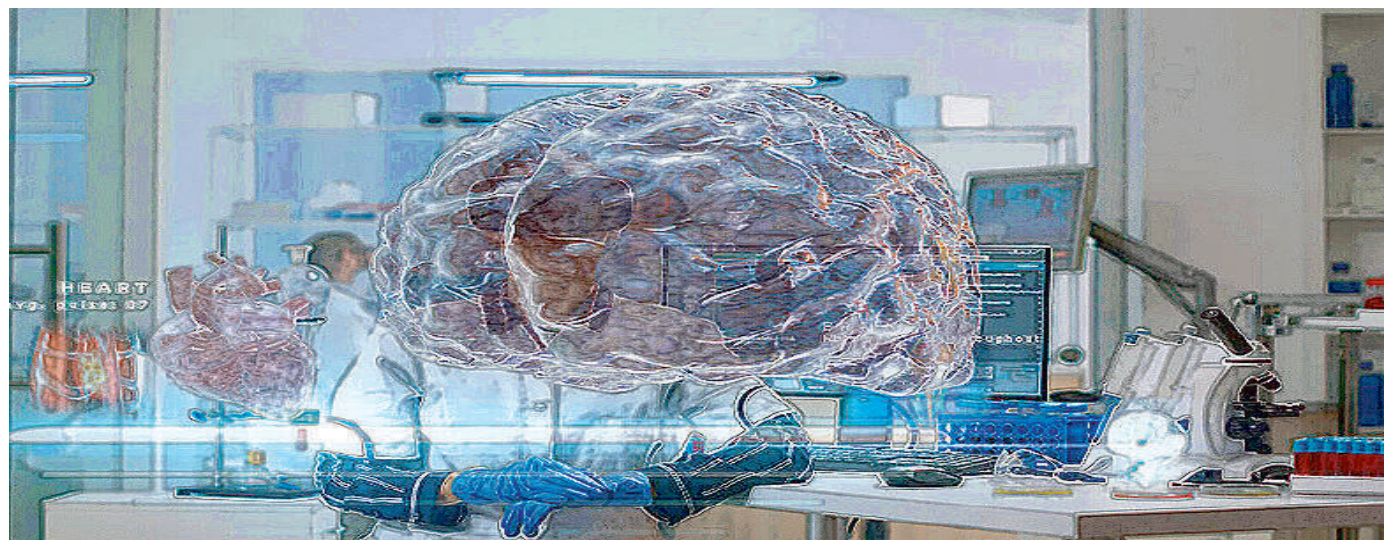

दृश्य प्रदान करता है। उल्लेखनीय रूप से, टीम ने पश्चिम में समान परियोजनाओं की लागत के दसवें हिस्से से भी कम पर यह उपलब्धि हासिल की। आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर (एचटीआईसी) के प्रमुख शिवप्रकाशम के नेतृत्व में यह उपलब्धि आईआईटी मद्रास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की एक संयुक्त पहल है। संभावित रूप से तंत्रिका विज्ञान और भ्रूण चिकित्सा में प्रमुख प्रगति के लिए चरणविकास संबंधी विकारों के शीघ्र निदान से लेकर तंत्रिका संबंधी रोगों की उत्पत्ति को समझने तक के अनुप्रयोग। इस शोध के संभावित अनुप्रयोग विशाल हैं। इस स्तर पर मस्तिष्क का विस्तार से अध्ययन करके, वैज्ञानिकों को नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी कि न्यूरोलॉजिकल रोग कैसे विकसित होते हैं, बायोमार्कर उनकी शुरुआत का संकेत देते हैं, और विभिन्न उपचार समय के साथ मस्तिष्क के कार्य को कैसे प्रभावित करते हैं। डिजिटल ब्रेन एटलस शोधकर्ताओं को अल्जाइमर जैसी बीमारियों के शुरुआती संकेतकों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे लक्षणों के गंभीर होने से पहले शीघ्र निदान और अधिक प्रभावी हस्तक्षेप संभव हो सकेगा। यह भारत जैसे देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां महंगे निदान उपकरणों तक पहुंच सीमित है और लाखों लोग तब तक निदान नहीं कर पाते हैं जब तक उपचार के लिए सार्थक अंतर लाने में बहुत देर नहीं हो जाती। सामर्थ्य पहलू परियोजना के मिशन के लिए केंद्रीय है, टीम ने अपने उपकरण और अंतर्दृष्टि को लागत के एक अंश पर उपलब्ध कराने, इस महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है कि इससे हर जगह रोगियों को लाभ हो। ब्रेन एटलस भारत में नवाचार के लिए एक नए मॉडल का भी प्रतिनिधित्व करता है, जहां सामर्थ्य और मापनीयता आवश्यक है। वर्षों से, तंत्रिका विज्ञान और एआई जैसे क्षेत्रों में अधिकांश अत्याधुनिक शोध पश्चिम में केंद्रित रहे हैं। आईआईटी मद्रास साबित कर रहा है कि भारत के पास न केवल भाग लेने के लिए बल्कि सफलताओं की अगली लहर का नेतृत्व करने के लिए प्रतिभा और रचनात्मकता है। कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस कार्य के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है। कम लागत पर नवप्रवर्तन करने की भारत की क्षमता इसे वैश्विक समस्याओं के समाधान में अद्वितीय लाभ प्रदान करती है। यदि समाधान भारत में काम कर सकते हैं, जहां संसाधन अक्सर कम होते हैं, तो वे हर जगह प्रभावी होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यह लोकतंत्रीकरण ब्रेन एटलस परियोजना के मिशन का केंद्र है। इस तरह का परिवर्तनकारी कार्य इन्फोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन जैसे दूरदर्शी दाताओं द्वारा संभव हुआ है, जिन्होंने अपने पोस्ट-कॉर्पोरेट करियर को वैश्विक प्रभाव के साथ अनुसंधान का समर्थन करने के लिए समर्पित किया है। सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर में उनका निवेश इस विश्वास को दर्शाता है कि भारत मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए किफायती, स्केलेबल समाधान बनाने में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इस साल की शुरुआत में आईआईटी मद्रास में अभूतपूर्व काम को प्रत्यक्ष रूप से देखने से मुझे उनके साथ सहयोग करने और अपनी कंपनी, वियोनिक्स बायोसाइंसेज के आर एंड डी को भारत में स्थानांतरित करने, उन्नत नैदानिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। अत्याधुनिक विज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने की उनकी प्रतिबद्धता नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने के मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। ये इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं कि सामर्थ्य और वैश्विक सहयोग में निहित भव्य दृष्टिकोण, उद्योगों को कैसे बदल सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इंटेलिजेंट बैक्टीरिया!

विजय गर्ग

कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे इंटेलिजेंट बैक्टीरिया को तैयार किया है, जो गणित की समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोलकाता के साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में कम करने वाले सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट संग्राम बाग ने एक बड़ी सफलता पा ली है। उन्होंने एक इंटेलिजेंट बैक्टीरिया बनाया है। ये बैक्टीरिया किसी नंबर में प्राइम नंबर की पहचान कर सकता है। साथ ही अल्फाबेट्स में वॉवल की पहचान कर सकता है। ये भारत के लिए बड़ी सफलता है। आइए इस बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं।

कंप्यूटिंग करने वाले बैक्टीरिया

साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में काम करने वाले संग्राम बाग ने लैब में ऐसे बैक्टीरिया को तैयार किया है, जो यह तय कर सकता है कि दी गई कोई संख्या प्राइम नंबर है या कोई अल्फाबेट स्वर है। संग्राम ने बताया कि पहले ये केवल 'मनुष्यों या कंप्यूटरों द्वारा किया जा सकता था, लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियर से तैयार किए गए बैक्टीरिया भी यही कर रहे हैं।

बता दें कि बैक्टीरिया सिंगल सेल के बने होते हैं, मगर वे अपने आसपास के वातावरण के लिए संवेदनशील होते हैं और प्रतिक्रिया भी देते हैं। वहीं बहुकोशिकीय जीव जैसे डॉल्फिन, चिम्पांजी, ऑक्टोपस, कौवे और मनुष्य को बुद्धिमान जीवों में गिना जाता है। इनमें करोड़ों ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं।

बैक्टीरिया में जेनेटिक सर्किट

बाग की टीम ने बताया कि उन्होंने बैक्टीरिया में 'जेनेटिक सर्किट' पेश किए, जिन्हें रासायनिक प्रेरकों (केमिकल सब्सटेंस, जिसका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है) के कॉम्बिनेशन से एक्टिव किया जा सकता था। इसके बाद टीम ने बैक्टीरिया को अलग-अलग इंजीनियर सर्किट के साथ मिलाकर एक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया के 'कंप्यूटर' बनाए, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स नेटवर्क की तरह व्यवहार करते थे। इस सेटिंग में इंजीनियर बैक्टीरिया का हर प्रकार एक 'बैक्टोन्यूरॉन' था और बैक्टोन्यूरॉन के कॉम्बिनेशन बिल्कुल बहुकोशिकीय जीव की तरह गणित पर प्रतिक्रिया कर रहे थे।

मेडिकल साइंस में विकास

टीम ने सितंबर में नेचर केमिकल बायोलॉजी में अपनी फाइंडिंग की रिपोर्ट की। इस पेपर ने सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट जीवों में नई क्षमताओं की इंजीनियरिंग करने वाले एक्सपर्ट के बीच रुचि पैदा की है। कोच्चि के सी.वी. जे. सेंटर फॉर सिंथेटिक बायोलॉजी एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग के एग्जीक्यूटिव डाय पवन धर ने कहा कि हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां बैक्टीरिया को केमिकल कॉन्वर्सेशन के जरिए मैथ प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि इन बैक्टीरियल कंप्यूटर्स के आने से फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस और बायो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में विकास हो सकता है।

स्क्रीन से परे: हमारे सोशल मीडिया जीवन की छिपी सच्चाइयाँ

विजय गर्ग

सोशल मीडिया जीवन को अधिक जुड़ा हुआ और दिलचस्प बनाने का एक उपकरण है, यह परिवार और दोस्तों की योग्यता और सफलता को आंकने का पैमाना नहीं है जब से सोशल मीडिया हमारे जीवन में घुसा है, हमने इसे अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों को प्रदर्शित करने की जगह बना लिया है। हम अपनी डिजिटल दीवारों को मील के पत्थर, यादों, मुस्कुराहट और दुखों से रंगते हैं। यह जीवन के विविध रंगों का एक जीवंत कोलाज है, फिर भी हम जो पोस्ट करते हैं वह अक्सर वास्तविकता का एक क्यूरेटेड संस्करण होता है। मुस्कुराहट उज्ज्वल है, प्यार गहरा है, छुट्टियाँ अधिक भव्य हैं, और दिल टूटना अधिक नाटकीय है। लेकिन फ़िल्टर की गई पूर्णता के इस लिबास के पीछे, कच्चा और अनफ़िल्टर्ड सच अक्सर दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ चुपचाप छिपा रहता है। एक महीने के लिए, मैंने अपनी छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट कीं - प्राचीन परिदृश्य, खुशनुमा भोजन और स्टाइलिश गेटअप - जिससे यह आभास हुआ कि मैं पृथ्वी पर सबसे खुश और भाग्यशाली व्यक्ति था। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे जीवन आनंद और संतुष्टि का एक सहज चित्रपट है। लेकिन हर पोस्ट के पीछे एक व्यक्तिगत लड़ाई चुपचाप लड़ी जा रही थी। जबकि मेरी टाइमलाइन बेलगाम खुशी बिखेर रही थी, मैं एक कठिन स्वास्थ्य चुनौती का समाधान करने के लिए खुद पर काम कर रहा था। जब मेरी वास्तविकता उथल-पुथल भरी थी तो मैंने ख़ुशहाल तस्वीरें पोस्ट करना क्यों चुना? क्या मैं नाटक कर रहा था? क्या मैं सत्यापन चाह रहा था? नहीं, मैं खुद को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने आप को याद दिला रहा था कि खुशी मौजूद है, सुंदरता और खुशी के क्षण अभी भी मेरे जीवन में विराम लगाते हैं। वे पोस्ट छल नहीं थे; वे जीवनरेखा थे। ख़ुशी की झलकियाँ जिनसे मैं जुड़ा रहा जब मैंने अपने भीतर के तूफ़ान को पार किया। और उन पलों को साझा करते हुए, मैं उन लोगों तक आशा की किरणें पहुंचाने की भी उम्मीद कर रहा था जो अनदेखी लड़ाइयां लड़ रहे होंगे। ये सोशल मीडिया का दोहरापन है. हम जो हँसी देखते हैं वह भेष में आँसू हो सकती है। भव्य समारोह चिंता में डूबा हो सकता है। सार्वजनिक रूप से बहाए गए आँसू प्रभाव के लिए गढ़े जा सकते हैं। जो प्रामाणिक प्रतीत होता है वह कृत्रिम हो सकता है; जो चीज़ लापरवाह दिखती है उस पर बोझ की परत चढ़ सकती है। यही कारण है कि हमें दूसरों को उनके प्रोफाइल पर जो दिखता है उसके आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। लोग अपने संघर्षों को छिपाकर ख़ुशहाल तस्वीरें क्यों पेश करते हैं? यह जरूरी नहीं कि यह धोखा हो या दूसरों को गुमराह करने की इच्छा हो। कभी-कभी, यह आशा को जीवित रखने का एक तरीका है। जब जीवन की चुनौतियाँ भारी पड़ जाती हैं, तो ख़ुशी का अनुमान लगाना एक स्व-पूर्ण भविष्यवाणी की तरह महसूस हो सकता है। खुशी साझा करके, भले ही वह पहुंच से बाहर हो, हम उसे प्रकट करने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि खुशी कोई भ्रम नहीं है - यह निकट है और हमारी मुट्ठी में है। हम इसे दूसरों के लिए भी करते हैं. सोशल मीडिया नकारात्मकता, तुलना और परेशान करने वाली खबरों से भरी एक अंधेरी और जबरदस्त जगह हो सकती है। सौंदर्य, प्रेम और हास्य के क्षणों को साझा करके, हम उन लोगों को सकारात्मकता की छोटी खुराक प्रदान करते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन यहीं जाल है. जब हम दूसरों के जीवन को सोशल मीडिया के चमकदार चश्मे से देखते हैं, तो हम तुलना के गड्ढे में गिरने का जोखिम उठाते हैं। हम अपने स्वयं के जीवन को दूसरों के प्रतीत होने वाले आदर्श जीवन के मुकाबले मापते हैं और आश्चर्य करते हैं कि हम कहाँ गलत हो गए। हम ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण या अपर्याप्त महसूस करते हैं। लेकिन यह तुलना अनुचित है—क्योंकि यह अधूरी जानकारी पर आधारित है। आप सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वह एक हाइलाइट रील है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। अपनी पर्दे के पीछे की वास्तविकता की तुलना किसी और की सावधानी से चुनी गई हाइलाइट्स से करना अपने आप को अनावश्यक पीड़ा के लिए तैयार करना है। तो, हमें सोशल मीडिया पर स्पष्टता और दयालुता के साथ कैसे संपर्क करना चाहिए? सबसे पहले, बिना ईर्ष्या के दूसरों की ख़ुशी में हिस्सा लें। उनकी खुशियाँ मनाएँ जैसे आप चाहते हैं कि वे आपकी खुशियाँ मनाएँ। उनकी ख़ुशी को एक अनुस्मारक बनने देंअच्छी चीजें संभव हैं, भले ही वे अभी तक आपके जीवन में नहीं आई हों। दूसरा, कठिन समय में बिना निर्णय किए सहायता प्रदान करें। यदि कोई अपना संघर्ष साझा करता है, तो उसे कमज़ोर करने या ख़ारिज करने की इच्छा का विरोध करें। उनके शब्दों के पीछे उनके द्वारा व्यक्त किये गए दर्द से कहीं अधिक गहरा दर्द हो सकता है। सहानुभूति प्रदान करें, धारणाएँ नहीं। स्थिर उपस्थिति बनें जो उन्हें याद दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। अंत में, सोशल मीडिया को ही लें - यह जीवन को अधिक जुड़ा हुआ, अधिक रोचक और कभी-कभी अधिक मज़ेदार बनाने का एक उपकरण है। यह मूल्य, सफलता या खुशी का पैमाना नहीं है।

अंतरिक्ष बुहारने की जरूरत : विजय गर्ग

विजय गर्ग

दुनिया के एक मशहूर कारोबारी और टेस्ला तथा एक्स (पूर्व में ट्विटर) के मालिक की दूरसंचार कंपनी 'स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज' फिलहाल करीब सौ देशों को इंटरनेट सेवाएं दे रही है। इस कंपनी की बातचीत भारत से भी चल रही है। उम्मीद है कि यह देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी तेज और सस्ती इंटरनेट सेवाएं देने में प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से होड़ करेगी। आज इंटरनेट तमाम सुविधाओं का वाहक बन गया है, इसकी बदौलत जो डिजिटल क्रांति आई है, उसने कई कामकाज आसान कर दिए हैं। अब तो कृत्रिम बुद्धिमता की तकनीक भी इसी इंटरनेट के कंधे पर सवार होकर नए गुल खिला रही है। मगर इसी इंटरनेट के रास्ते कई फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं। इनसे पूरी दुनिया परेशान है। एक समस्या इसकी वजह से पैदा हो रहे मानसिक प्रदूषण और डेटा के रूप में जन्म ले रहे कचरे की है, जिस पर ज्यादा विचार नहीं हो रहा है। मगर यह इंटरनेट अब अंतरिक्ष में कचरे की भरमार का कारक भी बन गया है। यानी दूरसंचार क्रांति धरती पर ही अनेक तरह का कबाड़ पैदा नहीं कर रही है, बल्कि अंतरिक्ष में जिन उपग्रहों की बदौलत इंटरनेट हम तक पहुंच रहा है, वे भी समस्याएं बढ़ा रहे हैं।

अंतरिक्ष में कचरा कोई नई समस्या नहीं है। सितारों के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारा कचरा पहले ही हमारे नजदीकी अंतरिक्ष में मौजूद रहा है। उसके खतरे पहले से कायम हैं। पर जब से अंतरिक्ष इंसानी गतिविधियों का केंद्र बना है, वहां इस कचरे ने और ज्यादा खतरनाक रूप धर लिया है। हम जिस इंटरनेट पर आज इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं, उसे हम तक पहुंचाने के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल हो रहे उपग्रह अंतरिक्षीय कबाड़ की बड़ी वजह बन गए हैं। ये उपग्रह अंतरिक्ष में मुख्यतः दो स्थानों पर हैं। एक तो पृथ्वी की निचली कक्षाओं में, जहां खासतौर से अकेले 'स्टारलिंक' ने अब तक 6764 उपग्रह पहुंचा दिए हैं। इनमें से 6714 काम कर रहे हैं, जबकि शेष कबाड़ होकर चक्कर काट रहे हैं। 'स्टारलिंक' की मदद करने वाली एलन मस्क की ही एक और कंपनी 'स्पेसएक्स' की योजना आगामी वर्षों में 42 हजार उपग्रह और भेजने की है, ताकि दुनिया में चप्पे-चप्पे तक इंटरनेट पहुंचाया जा सके। 'स्टारलिंक' ने वर्ष 2019 में अपना पहला दूरसंचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। इसके अगले पांच साल में ही उसके उपग्रहों की संख्या साढ़े छह हजार पार गई।

अंतरिक्ष की ऊपरी कक्षाओं में भारत समेत दुनिया के कई देशों के 3135 संचार उपग्रह पहले से ही हैं। अभी तक का आकलन कहता है कि पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 14 हजार से ज्यादा उपग्रह मौजूद हैं, जिनमें से करीब 3500 निष्क्रिय यानी कबाड़ हो चुके हैं। इस कबाड़ पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था 'स्लिंगशाट एअरोस्पेस' का कहना है कि ये निष्क्रिय उपग्रह कचरा बन गए हैं। इसके अलावा तमाम अन्य अंतरिक्षीय गतिविधियों से हमारे करीबी अंतरिक्ष में बारह करोड़ से ज्यादा छोटे-बड़े मलबे के टुकड़े तेजी से चक्कर काटने लगे हैं। असल में, इसके खतरे दो तरह के हैं। एक जितनी बड़ी संख्या में नए उपग्रह विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं, अचानक किसी दिन वहां मौजूद कचरा उनके रास्ते में आ सकता है और पूरे मिशन को खत्म कर सकता है। दूसरे, जिस तरह की भीड़ पृथ्वी की निचली कक्षा में हो गई है, वहां चक्कर काटते उपग्रहों से ही इस कचरे का विनाशकारी आमना-सामना हो सकता है।

कोई देश यह नहीं बताता कि उसके किस उपग्रह का मकसद क्या है और वह आखिर कितने उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने वाला है। इसकी वजह यह है कि इन उपग्रहों के दोहरे उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों ही हैं। सिर्फ सरकारें नहीं, निजी कंपनियां भी कारोबारी हितों के मद्देनजर इनसे जुड़ी जानकारियां नहीं बताती हैं। ऐसी स्थितियों का परिणाम क्या हो सकता है, इसकी एक नजीर

इसी वर्ष जून और अगस्त में मिली थी। जून में एक रूसी उपग्रह विस्फोट के साथ फट गया, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उससे छिटके कचरे की जद में आने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद अगस्त में अंतरिक्ष में काफी ऊंचाई पर पहुंचा एक चीनी राकेट फटा तो उसके टुकड़े मलबे की शक्ल में अंतरिक्ष में फैल गए।

x वर्ष 2021 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष संस्था को बताया कि एलेन मस्क की कंपनी 'स्पेसएक्स' की ही एक इकाई 'स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज' के उपग्रह दो बार चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के बहुत पास आ गए थे। पहली जुलाई और 21 अक्तूबर 2021 को हुई इन घटनाओं को लेकर चीन ने काफी नाराजगी दिखाई थी। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष मामलों के दफ्तर की वेबसाइट के मुताबिक 'स्पेसएक्स' के उपग्रहों के बेहद नजदीक आ जाने की स्थिति को देखते हुए चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में किसी टक्कर से बचने की उपायों को लागू कर दिया था, जिससे इसका कामकाज प्रभावित हुआ था। मसला अकेले चीन के लिए नहीं है। ऐसे मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'स्लिंगशाट' का आकलन है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों के अत्यधिक नजदीक आ जाने की घटनाओं में एक साल के अंदर ही 17 फीसद का इजाफा हुआ है। चूंकि इस निचली कक्षा में 'स्टारलिंक' के उपग्रहों का बोलबाला है, इसलिए इसकी मूल कंपनी 'स्पेसएक्स' को टक्कर रोकने वाले कई उपाय खुद करने पड़ते हैं। दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों को भी ऐसे उपाय करने पड़ रहे हैं। जैसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि बीते एक साल में उसके उपग्रहों को टकराव रोकने के लिए औसत से तीन या चार गुना ज्यादा उपाय करने पड़े हैं।

प्राकृतिक गतिविधियों पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण अंतरिक्ष में पैदा हो रहे कचरे की रोकथाम कुछ अर्थों में जरूर संभव है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल का सुझाव है कि इंसानी गतिविधियों से अंतरिक्ष में पैदा हो रहे कबाड़ को रोकने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर कोई तालमेल बनाया जाए। मगर समस्या यह है कि ज्यादातर देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर गोपनीयता बरतते हैं। निजी अंतरिक्ष एजेंसियां भी तकनीक के चोरी होने के भय से आंकड़े साझा नहीं करतीं। इसके अलावा चूंकि लंबी दूरी की बहुराष्ट्रीय मिसाइलों के निर्माण और जासूसी के काम में उपग्रहों का इस्तेमाल अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों का सटीक डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता। एक दूसरे पर अविश्वास की इस स्थिति में कोई बदलाव तभी संभव है, जब संयुक्त राष्ट्र इसमें दखल दे। जाहिर है कि जब तक ऐसा नहीं होता, अपने घर को भीतर से बुहारने वाली और सारा कचरा दरवाजे के बाहर ठेलने वाली मानव सभ्यता के लिए अंतरिक्ष की बिगड़ती सेहत एक समस्या ही बनी रहेगी।

इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं, क्या सरकार से मिलेगी जरूरी मदद?

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक दूसरा सबसे अधिक फलने-फूलने वाला सेक्टर है। इस क्षेत्र में अभी भी अपार संभावनाएं है और इसे केंद्र से सतत सहयोग की दरकार है। इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमी भी चाहते हैं कि विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार रियायतें देने के साथ ही बजटीय प्रावधान भी करे।

देहरादून। पर्यावरणीय दृष्ट से संवेदनशील उत्तराखंड में औद्योगिक विकास किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र का विषम भूगोल और पर्यावरणीय परिस्थितियां औद्योगिक विकास की राह में दुश्वारियां खड़ी करते आए हैं। इस सबको देखते हुए राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर विशेष जोर दिया जाता आ रहा है, जो यहां की पर्यावरणीय परिस्थितियों के एकदम अनुकूल है।

यही कारण है कि यह प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद दूसरा सबसे अधिक फलने-फूलने वाला सेक्टर है। इस क्षेत्र में अभी भी अपार संभावनाएं है और इसे केंद्र से सतत सहयोग की दरकार है। इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमी भी चाहते हैं कि विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार रियायतें देने के साथ ही बजटीय प्रविधान भी करे।

उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की तस्वीर देखें तो यह अभी तक मुख्य रूप से रुड़की, रुद्रपुर, सितारगंज, देहरादून, हरिद्वार व कोटद्वार इसके बड़े केंद्र हैं। यहां इलेक्ट्रिक बल्ब से लेकर कंप्यूटर व ड्रोन तक बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक का सालाना कारोबार तकरीबन 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। इसमें तकरीबन तीन लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

यद्यपि, राज्य से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में मशीनरी व यांत्रिक उपकरणों की भागीदारी 9.07 प्रतिशत है, जिसे सरकारी प्रोत्साहन मिलने पर बढ़ाया जा सकता है। राज्य में स्थापित इलेक्ट्रानिक उद्योग अपनी-अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियों की भी भरमार है।

जिन औद्योगिक क्षेत्रों में यह इकाइयां हैं, वहां सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही लाजिस्टिक और परिवहन नेटवर्क कमजोर होने के कारण उत्पादन व आपूर्ति की श्रृंखला प्रभावित हो रही है। उद्योगों को कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। कच्चे माल की उपलब्धता न होने के कारण इसके लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

काशीपुर में बन रहा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर

काशीपुर में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से संचालित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के तहत इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही आर्थिक वृद्धि हो सकेगी।

क्या चाहते हैं उद्यमी?

प्रदेश में एक मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो।

इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कुशल कार्यबल की हो उपलब्धता।

प्रौद्योगिकी व नवचार के लिए अनुसंधान में किया जाए निवेश।

राज्य और केंद्र की नीतियों में स्पष्टता और स्थिरता जरूरी।

संकट में है बंगाल का जूट उद्योग, अब केंद्र से मदद की गुहार

आयात में वृद्धि और बढ़ती परिचालन लागत से जूट इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ रहा है। यह इंडस्ट्री मांग में गिरावट की वजह से अपनी उत्पादन क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही है। जूट उद्योग का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियां चली गई हैं। इसका असर जूट किसानों पर भी पड़ा है जो अपनी उपज बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

कोलकाता। जूट बोरियों की लगातार घटती मांग से बंगाल के जूट उद्योग को इन दिनों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आयात में वृद्धि और बढ़ती परिचालन लागत ने भी उद्योग को परेशान कर रखा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में सालाना 38-39 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ में 500 बोरियां) की होने वाली मांग में भारी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 30 लाख गांठ रहने की उम्मीद है।

देश में जूट मिलों के शीर्ष संगठन भारतीय जूट मिल संघ (आईजेएमए) ने केंद्र सरकार से जूट बोरियों की घटती मांग और श्रमिकों व किसानों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव सहित अन्य चुनौतियों से निपटने में उद्योग की मदद के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की है।

आईजेएमए के अध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता ने कहा मांग में गिरावट से क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे मिलों को पालियों में कटौती करने और परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गई हैं। इसका असर जूट किसानों पर भी पड़ा है, जो अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जूट उद्योग 55 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा है, जिससे 50,000 से अधिक श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि देश के कुल जूट उत्पादन में बंगाल का योगदान लगभग 70 प्रतिशत है। शेष 30 प्रतिशत में अन्य राज्य शामिल हैं। देश में कुल 94 जूट मिलें हैं, जिनमें अकेले 70 बंगाल में हैं। बंगाल में 40 लाख जूट किसान और चार लाख श्रमिक इस उद्योग पर निर्भर हैं।

आयातित गेहूं-धान की पैकेजिंग में भी जूट बोरियों का हो इस्तेमाल

मांग को बढ़ावा देने के लिए आईजेएमए ने केंद्र से आग्रह किया है कि सभी आयातित गेहूं, चाहे वह सरकारी सौदों के माध्यम से हो या निजी व्यापार के माध्यम से, जेपीएम (जूट पैकेजिंग मैटेरियल) अधिनियम, 1987 के अनिवार्य प्रविधानों के अनुसार जूट की बोरियों में पैक किया जाना चाहिए।

धान की पैकेजिंग के लिए सेकेंड हैंड बैग के बजाय नई जूट बोरियों के इस्तेमाल की ओर लौटने का भी सुझाव दिया है। गुप्ता ने कहा कि फिलहाल खाद्यान्न और चीनी की पैकेजिंग में क्रमशः 100 प्रतिशत व 20 प्रतिशत जूट बोरियों का इस्तेमाल अनिवार्य है, लेकिन चीनी के मामले में इसका भी सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

जूट उत्पादों पर डंपिंग-रोधी शुल्क की समीक्षा की मांग

आईजेएमए ने सरकार से बांग्लादेश और नेपाल से जूट उत्पादों पर डंपिंग-रोधी शुल्क (एडीडी) की समीक्षा का अनुरोध किया है। मौजूदा डंपिंग-रोधी शुल्कों के बावजूद बांग्लादेश और नेपाल अभी गैर सरकारी जूट सामान बाजार में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं, जिसका मूल्य 3,500 करोड़ रुपये है। जूट बेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन गोपाल माहेश्वरी का कहना है कि इस उद्योग का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान है।

म्यूचुअल फंड्स में निवेश का मास्टर प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

युवा निवेशक अपनी जोखिम लेने की क्षमता के कारण इक्विटी फंड्स में SIP से शुरुआत कर सकते हैं। निवेश में जोखिम और रिटर्न का संतुलन जरूरी है। जहां स्मॉल-कैप फंड्स ज्यादा रिटर्न देते हैं वहीं ये ज्यादा अस्थिर होते हैं। और उनमें रिस्क ज्यादा होता है। लार्ज-कैप फंड्स स्थिरता प्रदान करते हैं और नए या सावधान निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हैं।

नई दिल्ली। Finance Ke Funde की सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम म्यूचुअल फंड्स के प्रकार, उनके फायदे और निवेश के सही तरीकों के बारे में जानेंगे। इस एपिसोड में म्यूचुअल फंड्स को मुश्किल से आसान बनाने के लिए हमने बातचीत की VSN Financial Services के Director, Bhavesh Garg से।

म्यूचुअल फंड्स को अक्सर जटिल वित्तीय साधन माना जाता है, लेकिन सही जानकारी और योजना के साथ यह धन-संपत्ति बनाने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकते हैं। भावेश गर्ग ने हाल ही में म्यूचुअल फंड्स के प्रकार, उनके लाभ और निवेश की रणनीतियों पर अपने अनुभव साझा किए। आइए उनके मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहां पूरा देख सकते हैं।

म्यूचुअल फंड्स का वर्गीकरण

भावेश गर्ग के अनुसार, म्यूचुअल फंड्स को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

Equity Mutual Funds : यह कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं और लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए उपयुक्त हैं। इनके उप-प्रकारों में लार्ज-कैप, मिड-कैप, स्मॉल-कैप, और फ्लेक्सी-कैप फंड्स शामिल हैं।

Debt Mutual Funds : ये फंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं और स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं।

Hybrid Mutual Funds : ये इक्विटी और डेट का मिश्रण होते हैं, जो जोखिम और रिटर्न का संतुलन प्रदान करते हैं।

भावेश कहते हैं कि ₹4,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड विकल्पों में से सही चयन के लिए इन श्रेणियों की सरल समझ होना जरूरी है।₹

जोखिम और रिटर्न का गणित

निवेश में जोखिम और रिटर्न का संतुलन जरूरी है। जहां स्मॉल-कैप फंड्स ज्यादा रिटर्न देते हैं, वहीं ये ज्यादा अस्थिर होते हैं। और उनमें रिस्क ज्यादा होता है। लार्ज-कैप फंड्स स्थिरता प्रदान करते हैं और नए या सावधान निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हैं। भावेश गर्ग कहते हैं, ₹जोखिम और रिटर्न साथ-साथ चलते हैं। निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना चाहिए।₹

युवाओं के लिए निवेश की रणनीति

युवा निवेशक अपनी जोखिम लेने की क्षमता के कारण इक्विटी फंड्स में SIP से शुरुआत कर सकते हैं। भावेश कहते हैं, ₹नियमित निवेश करें और समय-समय पर SIP में टॉप-अप करते रहें। यह लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का सबसे सरल तरीका है।₹

आदर्श पोर्टफोलियो कैसे बनाएं?

भावेश के अनुसार, निवेशकों को 4 फंड्स का पोर्टफोलियो रखना चाहिए:

Large Cap Fund : स्थिरता के लिए।

Mid-Cap Fund : मध्यम विकास के लिए।

Small-Cap Fund : लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न के लिए।

Thematic Fund : विविधता और अतिरिक्त लाभ के लिए।

बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना कैसे करें?

भावेश कहते हैं, ₹मार्केट में उतार-चढ़ाव से घबराने के बजाय लंबी अवधि के अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। सरल, सटीक और लंबे समय तक टिके रहने वाला निवेश ही सबसे प्रभावी होता है।₹ भावेश गर्ग ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए तीन अहम सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरल शुरुआत करें और नियमित निवेश को आदत बनाएं, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार योजना बनाएं और SIP को अपनाएं और इसे बनाए रखें।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, ₹जल्दबाजी से बचें और अनुशासित निवेश करें। यही वित्तीय सफलता की कुंजी है।₹ उनके ये सुझाव म्यूचुअल फंड्स की उलझनों को सुलझाने और निवेशकों को आत्मविश्वास के साथ निवेश करने में मदद करते हैं। अगर आप भी Mutual Fund में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज से जुड़कर Mutual Fund के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निवेश के लिए रहें तैयार, 19 दिसंबर को खुलेंगे चार कंपनियों के आईपीओ

19 दिसंबर को चार कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इनमें डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड और सनाथन टेक्सटाइल्स शामिल हैं। इन सभी आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए 23 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने भी आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

नई दिल्ली। अगर आप आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में निवेश करते हैं तो तैयार रहिये। इस सप्ताह 19 दिसंबर को चार कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इस सप्ताह जो कंपनियां आईपीओ ला रही हैं, उनमें डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम, ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड और सनाथन टेक्सटाइल्स शामिल हैं। इन सभी आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए 23 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स का 840.25 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल (ओएफएस) पर आधारित है। इस आईपीओ में प्रमोटरों के 2.97 करोड़ इक्विटी शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 269-283 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

कॉनकार्ड एनवायरो सिस्टम आईपीओ के जरिये 500.33 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। आईपीओ में 175 करोड़ रुपये के नए शेयर और 325.33 करोड़ रुपये के प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 665-701 रुपये प्रति शेयर तय किया है।

इसी तरह, ट्रांसरेल लाइटिंग ने 839 रुपये के आईपीओ का प्राइस बैंड 410-432 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ में 400 करोड़ रुपये के नए शेयर और प्रमोटरों के 1.01 करोड़ शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। सनाथन टैक्सटाइल ने अपने 550 करोड़ रुपये के आईपीओ का प्राइस बैंड 305-321 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ में 400 करोड़ रुपये के नए शेयर और 150 करोड़ रुपये के प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे।

आनंद राठी स्टाक ब्रोकर्स ने जमा किए दस्तावेज

आनंद राठी समूह की ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने आईपीओ के जरिये 745 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, यह पूरा आईपीओ नए शेयरों पर आधारित होगा। यानी इस आइपीओ में प्रमोटर शेयरों की बिक्री नहीं की जाएगी।

सोलर पावर से चलने वाले कृषि वाटर पंप सिस्टम बनाने वाली कंपनी जीके एनर्जी लिमिटेड ने भी 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा किए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, इस आइपीओ में नए और प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। नए शेयरों की बिक्री से जुटाए जाने वाले 422.46 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी अपनी लंबी अवधि की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगी।

जेन जेड इम्प्लॉइज को लुभाने का नया तरीका, 'Pet Leave' से लेकर जिम की फीस तक दे रही हैं कंपनियां

परिवहन विशेष न्यूज

टेक कंपनियां Gen Z स्टाफ को लुभाने के लिए नए तरीके अपना रही हैं। वे युवा कर्मचारियों को अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताने और उनकी जिम फीस देने जैसी सुविधा दे रही हैं। कंपनियों का कहना है कि इस तरह के लाभ देने से युवा कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ेगी उनका काम में मन लगेगा और वे कंपनी के साथ लंबे वक्त तक बने रहेंगे।

नई दिल्ली। भारत की टेक कंपनियां अपने ऑफिस में अधिक से अधिक मिलेनियल और Gen Z इम्प्लॉइज को आकर्षित करने के नए और अनोखे तरीके अपना रही हैं। उन्हें असीमित सिक लीव के साथ पालतू जानवरों के साथ समय बिताने जैसी रियायत दी जा रही है। कंपनियां अपने युवा कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें अपने दादा-दादी के साथ रहने तक का समय दे रही हैं। रिसर्चर्स 1997 से 2012 के बीच पैदा लोगों के Gen Z रूप में परिभाषित किया जाता है। इन्हें अमूमन जूमर्स भी कहा जाता है।

डेलॉइट इंडिया और नैसकॉम के इंडिया टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग सर्वे 2024 के अनुसार, कई फर्म ₹वेलबीइंग डेज़ तय करती हैं और जॉइनिंग बोनस देती हैं। हालांकि, यह दो साल के क्लॉबैक से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारी दो साल से पहले कंपनी नहीं छोड़ सकता है।

कर्मचारियों की प्राथमिकता के साथ तालमेल

इस सर्वे में देश भर की 200 से अधिक टेक कंपनियां शामिल थीं। रिपोर्ट में कहा गया है, "जेन जेड यानी युवा पीढ़ी वर्क-लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ और प्रोफेशनल ग्रोथ को तवज्जो दे रही है। यही वजह है कि कंपनियां नई पीढ़ी के टैलेंट को आकर्षित करने और अपने साथ बनाए रखने के लिए नजरिए को बदल रही है।'

टेक कंपनियों का मानना है कि इस तरह के लाभ देने से युवा कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ेगी, उनका काम में मन लगेगा और वे कंपनी के साथ लंबे वक्त तक बने रहेंगे। कंपनियां एआई के साथ तालमेल बनाकर कर्मचारियों की आगे बढ़ने में भी मदद कर रही हैं। उनका फोकस ऑर्गनाइजेशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना भी है।

कर्मचारियों की वेलबीइंग के लिए खास पहल

कुछ कंपनी ऐसी भी हैं, जो वेलबीइंग बीक मनाती हैं और अपने कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी मिलती है। कंपनी वेलबीइंग इक्विपमेंट खरीदने के लिए कर्मचारियों को सालाना 25,000 रुपये देती है और उनकी जिम मेंबरशिप का खर्च भी उठाती है।

कुछ कंपनियों के कैलेंडर में ₹लाइव म्यूजिक डेज़ के अलावा ₹ग्रैंडपेरेंट्स डेज़ और ₹जर्नलिंग डेज़ भी शामिल हैं, ताकि सभी को काम पर आने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस बारे में कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की पहल से उन्हें तनावमुक्त होने और भरपूर ऊर्जा के साथ काम पर लौटने में मदद मिलती है।"

डेलॉइट इंडिया-नैसकॉम की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कैसे युवा टैलेंट पूल को अक्सर अपने काम के घंटे और यहां तक कि बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस करने के लिए लोकेशन चुनने का भी विकल्प दिया जा रहा है।

'संविधान लहराने के लिए नहीं होता, ये विश्वास का विषय', राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे शाह

परिवहन विशेष न्यूज

मंगलवार को संसद के उच्च सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई आरोप लगाए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में संविधान पर बहस पर बोल रहे हैं। वहीं आज ही लोकसभा में एक देश एक चुनाव का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को अब JPC के भेजने की तैयारी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, रहमारे देश की जनता और हमारे संविधान ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कहते थे कि हम कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।" उन्होंने कहा कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस मुकाम पर महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी सच होती दिखाई पड़ती है कि भारत माता अपनी देदीप्यमान ओजस्वी स्वरूप में जब खड़ी होंगी, तब दुनिया की आंखें चकाचौंध हो जाएगी और पूरी दुनिया रोशनी के साथ भारत की ओर देखेगी।

नई दिल्ली। मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री ने संविधान पर चर्चा का जवाब दिया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया सबसे ज्यादा विस्तृत और लिखित संविधान है। दो साल 18 महीने तक विस्तृत चर्चा हुई। शायद ही दुनिया का कोई संविधान होगा जो देश की जनता को कमेंट के लिए दिया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, रहमारे देश की जनता और हमारे संविधान ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कहते थे कि हम कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।र

राज्यसभा में अमित शाह की बड़ी बातें

अमित शाह ने कहा कि दुनिया सबसे ज्यादा विस्तृत और लिखित संविधान है। दो साल 18 महीने तक विस्तृत चर्चा हुई। शायद ही दुनिया का कोई संविधान होगा जो देश की जनता को कमेंट के लिए दिया गया।

अमित शाह ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में हुई बहस देश के युवाओं के लिए शिक्षाप्रद होगी। इससे देश के लोगों को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि किस पार्टी ने संविधान का सम्मान किया है और किसने नहीं। मैं सरदार पटेल को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनके संघर्ष के कारण ही देश दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हमारे देश की जनता और हमारे संविधान ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कहते थे कि हम कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।र

उन्होंने कहा कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस मुकाम पर महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी सच होती दिखाई पड़ती है कि भारत माता अपनी देदीप्यमान ओजस्वी स्वरूप में जब खड़ी होंगी, तब दुनिया की आंखें चकाचौंध हो जाएगी और पूरी दुनिया रोशनी के साथ भारत की ओर देखेगी।

कांग्रेस पर जमकर बरसे शाह

भाजपा ने 16 साल तक शासन किया और संविधान में 22 संशोधन किए। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक शासन किया और 77 संशोधन किए।दोनों पार्टियों ने संविधान में संशोधन किए हैं। संशोधनों को लागू करने के अलग-अलग तरीके हैं- कुछ संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, जबकि अन्य केवल औपचारिकता के तौर पर किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन के पीछे के उद्देश्यों की जांच करके किसी पार्टी के चरित्र और इरादों को समझा जा सकता है।

संविधान की रचना के बाद डॉ अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर एक बात कही थी कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, वह बुरा बन सकता है, अगर जिन पर उसे चलाने की जिम्मेदारी है, वो अच्छे नहीं हों। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है, अगर उसे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो। ये दोनों घटनाएं हमने संविधान के 75 साल के कालखंड में देखी हैं।

कांग्रेस ने किए सबसे ज्यादा संशोधन: शाह

संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था। संविधान समिति ने यह संशोधन इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी आम चुनावों का इंतजार करने को तैयार नहीं थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 19A जोड़ा गया था और इस बदलाव को जवाहर लाल नेहरू ने लागू किया था, जो उस समय प्रधानमंत्री थे।

उन्होंने कहा कि हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया। समय के साथ साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन इस जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभी ने स्वीकार किया था। इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के लिए प्रोविजन किया गया था। अभी कुछ राजनेता आए हैं और 54 साल की आयु में अपनेआप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि संविधान के प्रावधानों को बदलने का प्रोविजन आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में ही है।

संविधान लहराते किसी को नहीं देखा: शाह

अभी हाल में हुए चुनाव में हमने अजीबो-गरीब नजारा देखा। इतने साल चुनाव हुए, लेकिन मैंने आजतक किसी को आम सभाओं में संविधान को लहराते नहीं देखा। संविधान को लहराकर और झूठ बोलकर कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। संविधान लहराने और बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है।

फिर भी नहीं आई मौत, कानपुर में ट्रेन के आगे कूदे युवक के कटे पैर : हालत गम्भीर

सुनील बाजपेई

कानपुर। जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं बल्कि उस सत्ता के हाथ में होती है ,जिसे ईश्वर , अल्लाह या गॉड कहते हैं। कुल मिलाकर जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय जैसे इस आध्यात्मिक कथन की पुष्टि तब हुई जब नजीराबाद थाना क्षेत्र में आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के आगे छलांग लगाने वाले युवक के पैर तो कट गए लेकिन मृत्यु तब भी नहीं हुई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज मंगलवार की सुबह नजीराबाद थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की वजह के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक छलांग लगाने युवक का नाम बसंत लाल बताया गया है। उसने आत्महत्या की कोशिश क्यों की इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है।

जानकारी के मुताबिक नजीराबाद क्रॉसिंग के सामने आज मंगलवार को एक युवक ट्रेन के आगे कूद गया। वह यहां बाइक लेकर आया, फिर सड़क किनारे खड़ी की। उस समय तेज रफ्तार से ट्रेन भी चली आ रही थी .। वह जैसे ही पास आई। उसने छलांग लगा दी। युवक का धड़ रेलवे लाइन के दूसरी तरफ निकला। उसके दोनों पैर कट गए। लेकिन, मौत नहीं हुई। इसके बाद ट्रेन को रोक लिया गया। पुलिस आई। उसको लेकर अस्पताल पहुंची। हालत गंभीर होने पर हैलट में भर्ती कराया गयाजहां उसकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं बताई गई है।

नजीराबाद थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि उसके जेब में मिले दस्तावेज से पहचान करने की कोशिश की की गई। इस दौरान उसका नाम बसंत लाल उम्र लगभग 40 साल निवासी दर्शन पुरवा पता चला है। पुलिस ने बताया कि परिवारी जनों के सामने आने पर ही आत्महत्या का प्रयास किए जाने का सही कारण पता चल सकेगा। इस घटना से कोका-कोला क्रॉसिंग पर कई घंटे जाम भी लग रहा जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से खुलवाया।

अपील - सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें : मुशरफ खान

परिवहन विशेष न्यूज

सोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिए अपनी और पब्लिक की लाइफ को ख़तरे में ना डालें : सामाजिक चिंतक मुशरफ खान

सोशल मीडिया कंपनियों को खतरनाक और गैर-जिम्मेदार वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के अकाउंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए : सामाजिक चिंतक मुशरफ खान

आगरा,संजय साग़र सिंह। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ लोग अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना कदम उठा रहे हैं। यह लोग अक्सर जोखिमपूर्ण स्टंट, खतरनाक चैलेंजेस या असुरक्षित परिस्थितियों में फोटोज़ और वीडियो पोस्ट करते हैं, जिससे न केवल उनकी अपनी सुरक्षा पर असर पड़ता है, बल्कि दूसरों के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है।

इस गंभीर विषय पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक चिंतक वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने सभी से अपील करते हुए कहा,रसोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिए अपनी और पब्लिक की लाइफ को ख़तरे में ना डालें। इसके साथ ही, बच्चों, नवयुवकों और पब्लिक हित में सोशल मीडिया कंपनियों को खतरनाक और गैर-जिम्मेदार वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के अकाउंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इससे न केवल सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए हो सके।"

उन्होंने कहा, "ऐसे खुराफ़ाती लोग जो सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों, नवयुवकों और लोगों को अजनबी खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कई बार दुखद घटनाओं का कारण बन सकते हैं। यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।"

श्री खान ने आगे कहा, "सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ लोग अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना वीडियो बना कर पोस्ट करते हैं जिससे न केवल उनकी अपनी सुरक्षा पर असर पड़ता है, बल्कि दूसरों के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण विचार बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया कंपनियों को खतरनाक और गैर-जिम्मेदार वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के अकाउंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये लोग लाइक और फॉलोअर्स पाने के लिए अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।

उन्होंने अंत में यह भी कहा, "सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यूज़र्स ऐसे खुराफ़ाती और असुरक्षित कंटेंट को पोस्ट न करें। इसके लिए इन्हें कड़े नियम और मॉडरेशन प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि खतरनाक स्टंट्स और चैलेंजेस को बढ़ावा न मिले। इसके साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे कंटेंट को तेजी से पहचानने और हटाने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम और रिपोर्टिंग मेथड्स को बेहतर बनाना चाहिए। इससे न केवल यूज़र्स की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाएगा।

झारखंड का सर्वाधिक 70 चोरी के मोटरसाइकिल सरायकेला जिले से बरामद

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

सरायकेला, तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत के चलते झारखंड में एक साथ सर्वाधिक चोरी मोटरसाइकिल सरायकेला-खरसावां पुलिस द्वारा अंतर्जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 70 (सत्तर) मोटरसाइकिल बरामद किया गया है ।मंगलवार को पुलिस अधीक्षक सरायकेला-खरसावां को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि तमाड़ थाना क्षेत्र के तीन मोटरसाइकिल चोर कुचाई बाजार में मोटरसाइकिल चोरी करने आने वाले हैं। ऐसी सूचना थी कि इन लोगों के द्वारा पहले भी इस क्षेत्र के विभिन्न हटिया एवं बाजार से मोटरसाइकिल की चोरी किया गया हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक सरायकेला-खरसावाँ के द्वारा एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। गठित छापामारी दल के द्वारा प्राप्त सूचना का सत्यापन करते हुए 1. शंकर मांझी उर्फ संदीप, पिता स्वर्गीय धनंजय मांझी, ग्राम रायडीह मोड, थाना तमाड़, जिला रांची एवं 2. भूषण मछुआ, पिता विष्णु मछुआ, ग्राम रायडीह मोड, थाना तमाड़, जिला रांची को एक (01) चोरी के मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में शंकर मांझी एवं भूषण मछुआ के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ये लोग सरायकेला-खरसावां जिला के अलावा भी रांची, चाईबासा, खूंटी एवं जमशेदपुर जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, हटिया एवं मेला से विगत कुछ वर्षों में करीब 100 से अधिक मोटरसाइकिल चोरी किये हैं । इनके द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने के लिए 1. शिव मुंडा उर्फ शिबू मुंडा, पिता स्वर्गीय सोमा मुंडा, ग्राम- जोजोहातू , टोला सोसोड़ीह, थाना कुचाई (दलभंगा ओ0 पी0) जिला सरायकेला-खरसावां एवं 2. मंगल मुंडा, पिता गुरुवा मुंडा, ग्राम बडानी, थाना अड़की, जिला खूंटी को बराबर देते रहने की बात स्वीकार की गई और शिव मुंडा एवं मंगल मुंडा के द्वारा कुचाई , दलभंगा एवं अड़की थाना क्षेत्र के ग्रामीणों को बाद में गाड़ी संबंधित कागजात देने की बात बोलकर सभी गाड़ियों को बेचा जाता है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सूचना के आधार पर शिव मुंडा उर्फ शिबू मुंडा एवं मंगल मुंडा को गिरफ्तार किया गया एवं इन लोगों के निशानदेही पर उनके घर एवं उनके द्वारा जंगल में छुपा कर रखें चोरी के कुल 30 (तीस) मोटरसाइकिल को बरामद कर जप्त किया गया, जिन्हें ये लोग उसे निकट भविष्य में बेचने की फिराक में थे। अनुसंधान के क्रम में छापामारी दल द्वारा चोरी के अन्य 39 (उनतालीस) मोटरसाइकिल को बरामद कर जप्त किया गया है ।फरार अभियुक्तों के विरूद्ध छापामारी की जा रही है।

बरामदगी से अब तक सरायकेला, रांची, जमशेदपुर, खूंटी एवं चाईबासा जिला के कुल 25 कांडों का उद्भेदन हुआ है। पुलिस द्वारा शेष जप्त मोटरसाइकिल का सत्यापन किया जा रहा है, सत्यापन के क्रम में दर्जनों कांडो के उद्भेदन होने की संभावना है।

गिरफ्तार सभी अभियुक्त बहुत ही शातिर प्रवृत्ति के बताए जाते हैं , यह सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैला रखे थे कि पुराना मोटरसाइकिल खरीद कर बेचने का काम करते हैं। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा मोटरसाइकिलों का कागजात बाद में देने की बात बोलकर भी उन्हें बेच दिया जाता था।

इस संदर्भ में कुचाई (दलभंगा ओ0 पी0) थाना कांड सं0- 41/2024 दिनांक- 17/12/2024 धारा- 111/317(4) /317(5)/336(3) /338/340(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 दर्ज किया गया है।

सरायकेला खरसावाँ पुलिस आम लोगों से अपील कर कहा है कि दस्तावेजों के सत्यापनोपरांत ही कोई वाहन खरीदे तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर चोरी के मोटरसाइकिल को नहीं खरीदे।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों में. शंकर मांझी उर्फ संदीप, पिता स्वर्गीय धनंजय मांझी, ग्राम रायडीह मोड, थाना तमाड़, जिला रांची। भूषण मछुआ, पिता विष्णु मछुआ, ग्राम रायडीह मोड, थाना तमाड़, जिला रांची। शिव मुंडा उर्फ शिबू मुंडा, पिता स्वर्गीय सोमा मुंडा, ग्राम- जोजोहातू, टोला सोसोड़ीह, थाना कुचाई (दलभंगा ओ0 पी0) जिला सरायकेला-खरसावां ।. मंगल मुंडा, पिता गुरुवा मुंडा, ग्राम बडानी, थाना अड़की, जिला खूंटी।

सदैव गुंजायमान रहेगी उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले की थाप!

भारत ही नहीं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद ज़ाकिर हुसैन हमारे बीच अब नहीं रहे ।15 दिसंबर 2024 को 73 साल की उम्र में सेन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वे सांस की बीमारी (इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस) से ग्रस्त थे ।पाठकों को बताता चलूं कि उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था और वे तबला वादक उस्ताद अल्ला रक्खा के बेटे थे। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि उनका पूरा नाम जाकिर हुसैन अल्लारका कुरैशी था। यह भी बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि जाकिर हुसैन को पंडित रविशंकर ने उस्ताद कहा था। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन- 1988 में पद्मश्री तथा सन-2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो साल 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2016 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। जाकिर हुसैन पहले इंडियन म्यूजिशियन थे, जिन्हें यह निमंत्रण मिला था। यह भी एक तथ्य है कि जाकिर हुसैन ने अपना पहला शो सिर्फ

7 साल की उम्र में किया था। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि जाकिर हुसैन ने महज 11 साल की उम्र में ही अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट किया था। इसके बाद साल 1973 में अपना पहला एल्बम 'लिविंग इन द मैटेरियल वर्ल्ड' लॉन्च किया। संगीत के साथ ही उन्होंने उन्होंने 1989 की फिल्म 'हीट एंड डस्ट' में अभिनय भी किया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वे 66वें ग्रैमी अवॉर्ड समारोह में भारत के पहले संगीतज्ञ बने, जिन्होंने अलग-अलग श्रेणियों में एक साथ तीन ग्रैमी अवॉर्ड हासिल किए। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी संगीत के बीच दूरियों को कम किया था, जैसा कि उन्हें भारतीय संगीत के साथ ही पाश्चात्य संगीत की बहुत अच्छी जानकारी थी। सच तो यह है कि जाकिर हुसैन को रतबला का रॉकस्टारर कहा जाता था।1970 के दशक में उन्होंने पश्चिमी संगीतकारों के साथ काम करके भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने प्रसिद्ध गिटारवादक जॉन मैकलॉघलिन के साथ मिलकर रशक्तिर नामक एक फ्यूज़न म्यूज़िक बैंड बनाया था। यह बैंड भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज़ संगीत का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता था। उनके इस प्रयोग ने भारतीय संगीत को पश्चिमी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया।अपने शुरूआती दौर में वे ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करते थे और सीट न मिलने पर कोच में फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाया करते थे लेकिन तबला हमेशा उनकी गोद में रहता था। पाठकों को बताता चलूं कि जाकिर हुसैन ऐसे कलाकार थे जो अपने लंबे और घुंघराले बालों के लिए मशहूर थे। वे संगीत को मात्र एक कला ही नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम मानते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो संगीत उनके लिए मेडिटेशन था। पुराने जमाने में उनका टीवी पर चाय का विज्ञापन आखिर कौन भूल सकता है ? पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि ताज चाय के विज्ञापन में तबला बजाते हुए जाकिर हुसैन द्वारा बोला गया वाक्य 'वाह ताज बोलिए' तो आज एक आईकन बन चुका है। कहते हैं कि जाकिर हुसैन ने एक प्रस्तुति के दौरान तबले से महादेव के डमरू और महादेव के गणों के शंखनाद की धुन निकाल दी थी। उनकी इस प्रस्तुति को उस समय लोगों ने उन पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद बताया था। वे ऐसे संगीतज्ञ थे जिन्होंने कभी भी किसी निजी समारोह, कॉर्पोरेट कार्यक्रम या शादियों में प्रस्तुति नहीं दी। जाकिर हुसैन ने अपनी मैनेजर रही एनटोनिया मिनेकोला से शादी की, जो कि एक कथक डांसर व शिक्षक हैं। उन्हें दो बेटियां हैं, जिनके नाम अनीशा और इस्बेला कुरैशी हैं। कहते हैं कि उनकी उंगलियों और हाथ की थाप में जादू था। कहना ग़लत नहीं होगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अंत में यही कहूंगा कि आज भले ही जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं हैं लेकिन कला और संगीत के प्रति उनकी असीम साधना, उनके तबले की थाप दुनिया के हर किसी संगीत प्रेमी के दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। कहना ग़लत नहीं होगा कि वह अपने पीछे एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसे विश्व भर के असंख्य संगीत प्रेमी संजोकर रखेंगे। उनका जीवन भारतीय संगीत प्रेमियों और संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए आदर्श और हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। ताल के जादूगर की उंगलियों और हथेली की थाप ब्रह्मांड की गहराईयों से भी सदैव इस विश्व में गुंजायमान होती रहेगी।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

तबला और "वाह उस्ताद वाह"

तबले की थाप पर खूब बनी कहानियाँ,
लो खप ही गई इसमें भी कई जवानियाँ।
हर थाप में थी भावनाओं की गहराइयाँ,
उस पर भी तो लोग बना देते थे रुबाईयाँ!
याद आ ही जाती थी उन्हें भी तनहाइयाँ।
तबले की थाप पर खूब बनी कहानियाँ,
लो खप ही गई इसमें भी कई जवानियाँ।
भई कांट्रेक्ट में बंधे हो, मत काटना बाल,
लहराते हैं इसके साथ लय और सुर ताल!
"वाह उस्ताद वाह" कहे हमेशा पूरा हॉल।
तबले की थाप पर खूब बनी कहानियाँ,
लो खप ही गई इसमें भी कई जवानियाँ।
उंगलियों और हथेलियों की यह ध्वनियाँ,
हर ताल और लय सबको करती विस्मृत!
अविश्वसनीय गति कर देती थी चमत्कृत।
तबले की थाप पर खूब बनी कहानियाँ,
लो खप ही गई इसमें भी कई जवानियाँ।
सिर्फ तबला नहीं तबले से संवाद किया,
शास्त्रीय संगीत में जैज व फ्यूजन दिया!
जाकिर हुसैन साब ये क्या कमाल किया।

संजय एम तराणेकर

लोग खड़े होकर पी रहे थे चाय ट्रैक्टर ने दुकान में मारी टक्कर

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर्। कटक सेलर स्ट्रीट में बड़ा हादसा हुआ है। आज सुबह-सुबह कुछ लोग सेल्टर स्ट्रीट पर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। अचानक एक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह चाय की दुकान में जा घुसा। उस समय दुकानदार बाहर था। जिससे दुकानदार एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गया ।हादसे में चाय की दुकान पूरी तरह नष्ट हो गई। वहीं, वहां चाय पीने वाले ग्राहकों को भी बड़ा झटका लगा।

कोरापुट, कटक, जाजपुर जिला ब्लॉक अध्यक्षों सहित बिजेड़ी, कांग्रेस, कई सरपुच्य, समिति सदस्य भाजपा में शामिल हुए

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर : भाजपा सरकार ओडिशा को एक विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा की जनता के मन में नई बीजेपी सरकार को लेकर उत्साह का माहौल बन गया है। भाजपा की संगठनात्मक ताकत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल ने कहा कि ओडिशा की जनता का भाजपा सरकार पर भरोसा और विश्वास बढ़ रहा है। बिजेड़ी का कांग्रेस से भरोसा उठ गया है, जिसमें कोरापुट, कटक और जाजपुर जिले के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला बिजेड़ी उपाध्यक्ष और कई सरपुच्चा और SDC सदस्य भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस संदर्भ में, जयपुर ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में 13 सरपचस, 14 समिति सदस्य और 11 एसडीसी (विशेष विकास परिषद) सदस्य, जिनमें सरपचस श्री आनंद हलुआ, श्री टंकधर हलुआ और 11 एसडीसी (विशेष विकास परिषद) सदस्य शामिल हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं। कोरापुट की श्रीमती तिलोत्मा गुदुली। इसी तरह, कटक जिला बीजेडी के उपाध्यक्ष और पूर्व सरपचू, समिति सदस्य, प्रथम समिति के अध्यक्ष आदित्य पानी के नेतृत्व में, सरपचू मूर्ति मल्लिक के वार्ड सदस्य प्रफुल्ल कुमार साहू, प्रशांत साहू, गोबिंद चंद्र बेहरा, रीना स्वागीकु सहित 50 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जाजपुर जिले के विातालो रिट्रीट के पूर्व सरपाचू दिलीप मोहंती, रिट्रीट कमेटी की पूर्व सदस्य निरुपमा सेठी सहित सैकड़ों बीजद और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन ने सभी नये कार्यकर्ताओं को टोपी एवं उत्तरीय देकर स्वागत किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023